संपूर्ण भारत के लिए एक प्रकाशन
दैनिक घटती घटना
RNI REG. No.-CHHHIN/2004/15050
Po.Reg.No.-13/Sarguja DN/2023-2025
www.ghatatighatana.com
ghatatighatana11@gmail.com
अम्बिकापुर,वर्ष 21, अंक - 309 शनिवार 13 सितम्बर 2025, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये

भारत के 15 वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ,सितंबर 2030 तक होगा कार्यकाल

नई दिल्ली,12 सितम्बर 2025 (ए)। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक होगा। इस दौरान पीएम मोदी,गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। धनखड़ ने 21 जुलाई को हेल्थ इश्यू के कारण इस्तीफा दिया था। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15 वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले। राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया है। राधाकृष्णन ने 1998 और 1999 में कोयम्बटूर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता। 1998 में उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। 1999 में भी वे 55,000 वोटों से जीते। राधाकृष्णन एक बार केंद्रीय मंत्री बनने के बेहद करीब थे,लेकिन एक जैसे नाम के कारण पार्टी प्रबंधकों से चूक हुई और एक अन्य नेता पोन राधाकृष्णन को पद सौंप दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने शिकायत नहीं की और संगठन में सक्रिय रहे। राधाकृष्णन 2004 से 2007 तक तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष रहे और 19,000 किमी लंबी रथयात्रा निकाली। इसमें नदियों को जोड़ने,आतंकवाद खत्म करने, समान नागरिक संहिता लागू करने और नशे के खिलाफ आवाज उठाई। 2020 से 2022 तक वे भाजपा के केरल प्रभारी रहे। 2004 में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में शामिल हुए और ताइवान गए पहले संसदीय दल के सदस्य भी रहे। 2016 में उन्हें कोच्चि स्थित कॉयर बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उनके कार्यकाल में भारत का कॉयर निर्यात रिकॉर्ड 2,532 करोड़ रुपए तक पहुंचा।

राधाकृष्णन को उम्मीद से ज्यादा 14 वोट ज्यादा मिले

राज्यसभा के महासचिव और निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी के मुताबिक 781 में से 767 सांसदों ने वोट डाले,वोटिंग 98.2% हुई। इनमें से 752 मत वैलिड और 15 इनवैलिड थे। एनडीए को 427 सांसदों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने भी राधाकृष्णन का समर्थन किया। 13 सांसदों ने चुनाव में मतदान से परहेज किया। इनमें बीजू जनता दल के सात सांसद,भारत राष्ट्र समिति के चार,शिरोमणि अकाली दल का एक सांसद और एक निर्दलीय सांसद शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि एनडीए उम्मीदवार को उम्मीद से 14 वोट ज्यादा मिले,जिससे विपक्षी खेमे में क्रॉस-वोटिंग की अटकलें हैं।

राधाकृष्णन ने एक दिन पहले राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया

अपनी नई जिम्मेदारी की तैयारी में राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि की गई है। उनके इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

इस्तीफे के बाद पहली बार नजर आए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ हंसते-ताली बजाते दिखे

चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। लाल कुर्ता पहने राधाकृष्णन ने अंग्रेजी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। उन्होंने मंगलवार को विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराकर उपराष्ट्रपति चुनाव जीता था। समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे, जो 21 जुलाई के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। समारोह में वह राधाकृष्णन के पास पहली पंक्ति में हंसते-मुस्कुराते और ताली बजाते दिखे। धनखड़ ने राधाकृष्णन को पत्र लिखकर बधाई दी थी, जिसमें उन्होंने उनके अनुभव और नेतृत्व की सराहना की। विपक्षी दलों ने धनखड़ की 50 दिन से अधिक की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस ने उनकी गैरमौजूदगी को लेकर सरकार से जवाब मांगा था।

दिल्ली हाई कोर्ट में बम की अफवाह झूठी निकली

नई दिल्ली,12 सितम्बर 2025 (ए)। दिल्ली उच्च न्यायालय को शुक्रवार बम से उड़ाने की धमकी मिली। जांच-पड़ताल के बाद बम की धमकी झूठी निकली। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार अरुण भारद्वाज के ई-मेल पर बम की धमकी वाला मैसेज आया था। बम की धमकी सुबह 8.39 मिनट पर ई-मेल से मिली। ई-मेल में कहा गया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय में जजों के कमरे में तीन बम प्लांट किए गए हैं। ई-मेल में दो बजे तक कोर्ट परिसर खाली करने को कहा गया। बम की धमकी मिलने के बाद पूरे कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई। जज अपने अपने कोर्ट को छोड़कर चले गये। कोर्ट में बम निरोधक दस्ते और अग्निशमन दल को बुलाया गया। सुरक्षाकर्मियों ने सभी को कोर्ट परिसर खाली करने को कहा। बाद में पूरे कोर्ट परिसर की जांच की गई, लेकिन बम की धमकी झूठी निकली।

पूरे देश को साफ हवा का हक दिल्ली-एनसीआर ही क्यों,देशभर में पटाखे बैन होने चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 12 सितम्बर 2025 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में पटाखों को बैन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि अगर दिल्ली-ह्रष्टक्र के शहरों को साफ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं? प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ष्टछ्वढ्ढ गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो पूरे देश में बैन करना चाहिए। साफ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली-ह्रष्टक्र तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संबंधी जो भी नीति हो वह पूरे भारत में होनी चाहिए। हम सिर्फ दिल्ली के लिए इसलिए नीति नहीं बना सकते, क्योंकि यहां देश का एलीट क्लास हैं। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें दिल्ली-ह्रष्टक्र में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज, परिवहन और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को संशोधित करने की मांग की गई है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की घोषणा

कर्नाटक में नई जाति जनगणना 22 सितंबर से

बेंगलुरु,12 सितम्बर 2025 (ए)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में 22 सितंबर से 7 अक्तूबर तक एक नया सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि 2015 की जाति जनगणना को सरकार ने स्वीकार नहीं किया,और एक दशक बाद समाज की वर्तमान स्थिति जानने के लिए यह सर्वेक्षण जरूरी है। सिद्धारमैया ने कहा,संविधान सभी को समानता और सामाजिक न्याय का अधिकार देता है। यह सर्वेक्षण असमानताओं को दूर करने और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सर्वेक्षण में राज्य के लगभग सात करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को यूनिक घरेलू पहचान पत्र (यूआईडी) स्टिकर दिया जाएगा,जिसमें अब तक 1.55 करोड़ स्टिकर वितरित हो चुके हैं। सर्वेक्षण के लिए 60 प्रश्नों वाली प्रश्नावली तैयार की गई है, और 1.85 लाख सरकारी शिक्षकों को तैनात किया जाएगा,जिन्हें 20,000 रुपये तक का मानदेय मिलेगा।

सिक्किम में लैंडस्लाइड,4 की मौत

आगरा में 40 गांव डूबे,हिमाचल में बाढ़-बारिश से अब तक 380 की मौत

नई दिल्ली,12 सितम्बर 2025 (ए)। वेस्ट सिक्किम के यांगथांग के अपर रिंबी इलाके में शुक्रवार रात लैंडस्लाइड हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग लापता हैं। एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तेज धार नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी चल रहा है। यूपी के आगरा में यमुना में बाढ़ है। यहां 25 कॉलोनियां और 40 गांव में 2-5 फीट तक बाढ़ का पानी भरा है। ताजमहल के पीछे बना पार्क पूरी तरह से डूब गया। 5 हजार से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में हैं। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक बारिश-बाढ़ के कारण 380 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 लापता हैं।

नेपाल की पहली महिला पीएम बनीं सुशीला कार्की

फिलहाल कोई मंत्री नहीं,राष्ट्रपति का ऐलान- 6 महीने में होंगे चुनाव

काठमांडू,12 सितम्बर 2025 (ए)। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम बन गई हैं। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुक्रवार रात राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई। फिलहाल किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया है। राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगले छह महीनों के भीतर संसद का नया चुनाव कराया जाएगा। वहीं, Gen-Z नेताओं ने इस सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के कामकाज की निगरानी करेंगे। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकीं हैं। उन्होंने

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।

नेपाल में भारतीय राजदूत ने सुशीला कार्की को बधाई दी : नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने शपथ ग्रहण समारोह में सुशीला कार्की से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी।

नेपाल में कोई जज दूसरी बार पीएम बना : सुशीला कार्की पहली ऐसी शख्स नहीं हैं जो न्यायधीश बनने के बाद अंतरिम पीएम बनी हैं। पहली बार ऐसा 2013 को हुआ था, जब मुख्य न्यायाधीश खिलराज रेग्मी के नेतृत्व में चुनावी सरकार बनाई गई थी। पहली संविधान सभा के विघटन के बाद देश में राजनीतिक गतिरोध (रुकावट) पैदा हो गया था। इसे हल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने समझौता किया और रेग्मी को सरकार बनाने का जिम्मा दिया।

शपथ ग्रहण में उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस भी मौजूद थे...

लंबी रस्साकशी के बाद राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव,चीफ जस्टिस,नेपाल सरकार के कई बड़े अधिकारी और डिप्लोमैट मौजूद थे।

अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 2.07% पर पहुंची खाने-पीने का सामान महंगा होने का असर

नई दिल्ली,12 सितम्बर 2025 (ए)। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को झटका लगने वाली खबर है। खुदरा महंगाई दर अगस्त माह में मामूली रूप से बढ़कर 2.07 फीसदी पर पहुंच गई है। इससे पिछले महीने जुलाई में यह आठ साल के निचले स्तर 1.55 फीसदी रही थी। इसकी वजह कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) पर आधारित महंगाई अगस्त,2024 में 3.65 फीसदी थी। अगस्त में खुदरा महंगाई दर में वृद्धि की मुख्य वजह सब्जियों, मांस और मछली, तेल और वसा, व्यक्तिगत देखभाल और अंडे की महंगाई में वृद्धि के कारण है। एनएसओ के मुताबिक महंगाई के बास्केट में लगभग 50 फीसदी योगदान खाने-पीने की चीजों का होता है। इसकी महीने-दर-महीने की महंगाई माइनस 1.76 फीसदी से बढ़कर माइनस 0.69 फीसदी हो गई है। अगस्त महीने में ग्रामीण महंगाई दर 1.18 फीसदी से बढ़कर 1.69 फीसदी हो गई है। शहरी महंगाई 2.10 फीसदी से बढ़कर 2.47 फीसदी पर पहुंच गई है।

खुदरा महंगाई दर फरवरी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लक्ष्य 4 फीसदी से नीचे है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में मौद्रिक समीक्षा में पूरे वित्त वर्ष की महंगाई का अनुमान घटाकर 3.1 फीसदी कर दिया है, जो पहले 3.7 फीसदी था।

ऑपरेशन सिंदूर सेना के लिए रियलिटी चेक बना,हमें अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत,देश को आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी : रक्षा सचिव

पुणे, 12 सितम्बर 2025 (ए)। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सशस्त्र बलों के लिए एक रियलिटी चेक साबित हुआ है। इससे पता चला कि हमें भविष्य के लिए कई क्षेत्रों में अपनी ताकत को और मजबूत करने की जरूरत है। सिंह पुणे में हुए सदर्न कमांड डिफेंस टेक सेमिनार में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से पता चला कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर,एंटी ड्रोन सिस्टम,लो-लेवल रडार और बिना GPS वाले मिलिट्री-ग्रेड ड्रोन्स की कमी है। उन्होंने कहा,इन क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है। रक्षा मंत्रालय तुरंत जरूरी उपकरण खरीद रहा है, वहीं लंबे समय के लिए डीआरडीओ और निजी कंपनियों के साथ मिलकर स्वदेशी तकनीक पर

काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। इसका मकसद एलओसी पर और उसके पार मौजूद आतंकी बुनियादी ढांचे को सटीक और रणनीतिक तरीके से खत्म करना था। सिंह ने मल्टी-लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की भी तारीफ की। उनके कहा कि ऑपरेशन के दौरान यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में बेहद प्रभावी रहा और बड़े नुकसान से देश को बचा लिया। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 9 सितंबर को कहा कि युद्ध के दौरान जमीन पर कब्जा ही भारत में जीत की असली 'करेंसी' या पैमाना है। इस वजह से थल सेना की भूमिका हमेशा सबसे अहम रहेगी। जनरल द्विवेदी दिल्ली में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा-पिछले महीने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। उन्होंने भी सिर्फ जमीन के आदान-प्रदान को लेकर चर्चा की।

वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी कल्चर बंद,लाइव स्ट्रीम होंगे दर्शन

लखनऊ-मथुरा,12 सितम्बर 2025 (ए)। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेन्ट कमेटी की गुरुवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। कमेटी ने मंदिर के दर्शनों के समय जहां बढ़ा दिया है, वहीं वीआईपी पर्चियां अब नहीं बनेंगी। इसके साथ ही कमेटी ने मंदिर के प्रांगण में खाली स्थान पर (लगभग 357 गज) पर पूर्व में हुए अधूरे निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच कराने तथा 4.74 एकड़ जमीन खरीदने जैसे कई मुद्दों पर मंथन किया। गुरुवार को कमेटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायालय इलाहाबाद अशोक कुमार की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में बांके बिहारी मन्दिर में दर्शन के लिए वीआईपी पर्ची बंद किये जाने पर विचार मंथन हुआ।

बीरभूम में बड़ा हादसा : पत्थर की खदान धंसने से 5 मजदूरों की मौत,चार की हालत गंभीर

बीरभूम,12 सितम्बर 2025 (ए)। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शुक्रवार को पत्थर के खदान में अचानक धंसान होने से कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। इस दुर्घटना में अब तक पांच मजदूरों की मौत हो चुकी है जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत रामपुरहाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। उसे बाद में बर्दवान मेडिकल कॉलेज स्थानांतरित किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार,दोपहर के समय 10 से 12 मजदूर खदान में पत्थर निकालने का काम कर रहे थे,तभी अचानक खदान का एक हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। मजदूरों को बचने का कोई मौका नहीं मिला और वे पत्थरों के नीचे दब गए। घटना की सूचना पाकर आसपास

की खदानों के मजदूर और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। पांच मजदूरों के शव बाहर निकाले गए और घायल मजदूरों को अस्पताल भेजा गया। जिले के पुलिस अधीक्षक अमनदीप ने बताया कि पूरी घटना की जांच की जा रही है और फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि दुर्घटना कैसे हुई। एसपी के अनुसार,अभी तक पांच लोगों की मौत की आधिकारिक जानकारी सामने आई है। हालांकि, मौके पर मौजूद वाहन चालकों का दावा है कि इस हादसे में छह लोगों की मौत हुई है। हादसे की भयावहता को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। पुलिस और लोगों की मदद से राहत कार्य जारी है।

तेजस्वी यादव 16 सितंबर से शुरू करेंगे 'बिहार अधिकार यात्रा'

पटना,12 सितम्बर 2025 (ए)। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी रणनीतियों को और मजबूत करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर जनता के बीच पहुंचने की तैयारी में हैं। राजद ने घोषणा की है कि तेजस्वी यादव की 'बिहार अधिकार यात्रा' 16 सितंबर, 2025 से शुरू होगी और 20 सितंबर को इसका समापन होगा। इस यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से होगी, जबकि इसका समापन वैशाली में होगा। इस पांच दिवसीय यात्रा को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एक बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राजद ने अपने सभी विधायकों, जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी

ताकत लगाने के निर्देश दिए हैं। तेजस्वी यादव इस दौरान विभिन्न जिलों में जनता से सीधा संवाद करेंगे और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य,और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ 'वोटर अधिकार यात्रा' में हिस्सा लेकर बिहार की जनता के बीच मजबूत राजनीतिक संदेश दिया था। अब 'बिहार अधिकार यात्रा' के जरिए वे अकेले मैदान में उतरकर जनता के असली मुद्दों को उठाने और विपक्ष की एकजुटता को प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे।

भारत और यूरोपीय संघ ने एफटीए वार्ता के शीघ्र समापन की प्रतिबद्धता दोहराई : गोयल

नई दिल्ली, 12 सितम्बर 2025 (ए)। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने चल रही मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता को शीघ्र पूरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराई है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए दोनों पक्षों के लोगों और व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता का नेतृत्व करने के लिए यूरोपीय संघ के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफ्कोविक और कृषि एवं खाद्य आयुक्त क्रिस्टोफ हैनसेन तथा ईयू के प्रतिनिधिमंडल 12-13 सितंबर को दो दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इनके साथ रात्रि भोज पर मिले। गोयल ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा है कि मुझे अपने मित्र की मेजबानी करते हुए खुशी हो रही है।

उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ एफटीए पर वार्ता जारी रहने के साथ हम इसके शीघ्र समापन के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए दोनों पक्षों के लोगों और व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगा।

संपादकीय

जातीय संघर्ष जनजीवन अस्त-व्यस्त

वर्तमान में मणिपुर देश का एकमात्र राज्य है,जहां राष्ट्रपति शासन लागू है। मैतई-कुकी के खूनी संघर्ष के चलते इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।1967 के बाद से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने का ग्यारहवां उदाहरण है। अब मणिपुर अखंडता पर समन्वय समिति ने कुकी-जो समुदाय के दो प्रमुख संगठनों द्वारा सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। कोकोमी शांति स्थापित करने के लिए रोडमैप तैयार कर रहा है। केंद्र व राज्य सरकार ने कुकी-जो विद्रोही समूहों के साथ पनुर्निधारित नियमों, शर्तों या आधारभूत नियमों के साथ विशेष सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्रालय का कहना है कि नागरिक समाज संगठनों के इन समूहों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को यात्रियों और जरूरी वस्तुओं की आवाजाही के लिए खोलने पर सहमति व्यक्त की है। मई,2023 में राज्य में कुकी-मैतई के दरम्यान हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपेक्षित यात्रा को लेकर यह व्यवस्था किए जाने की चर्चा है। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमानुसार मोदी 13 सितम्बर को वहां जा सकते हैं। जातीय संघर्ष में ढाई सौ से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। जनजीवन अस्त-व्यस्त है। सरकारी इमारतों को क्षति पहुंचाने के अलावा स्थानीय रोजगार ठप पड़े हैं। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों ने आम नागरिकों के भीतर दहशत भर दी है। साठ हजार से ज्यादा लोग अपने घरों को अब तक लौट नहीं पाए हैं। सामान्य स्थिति की बहाली को लेकर जनता में निश्चितता देखी जा सकती है। हालांकि यह राजनीतिक दांव भी हो सकता है क्योंकि अरसे से मोदी के लगातार चुनावी रैलियों में शामिल होने पर विपक्ष निशाना साध रहा था।मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्र का उपेक्षाभाव देख सवाल उठना लाजिमी था। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आलोचनाओं को थामने के लिए मोदी की यह यात्रा हो सकती है, जहां कुछ योजनाओं का ऐलान कर वे अपने जिम्मेदाराना व्यवहार का अहसास कराना चाहेंगे। संघषर्ग्रस्त राज्य में शांति बहाली केंद्र को अपनी प्राथमिकताओं में रखना चाहिए। चुनावी चकल्लस के अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी को ख्याल रखना होगा कि देश के किसी भी कोने को उपेक्षित न रहने दिया जाए और शांति स्थापित करने के प्रति यथाशीघ्र विशेष सतर्कता बरती जाए।

ट्रंप के लाडले का मर्डर क्यों? दुनियाँ के सामने सबसे बड़ा सवाल?

किशन भावानी
गोंदिया,महाराष्ट्र

वक्तव्य देते समय वक्ताओं,मीडिया, नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि भाषा संयमित हो,उत्तेजना कम हो,लेकिन सक्रिय आलोचनाएँ हों,यह लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है...

आधुनिक युग को यदि सुविधाओं और संसाधनों का युग कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी,लेकिन इन सुविधाओं और विलासिताओं की कीमत भी समाज को चुकानी पड़ रही है। मशीनों और तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, परंतु इसके साथ ही ऐसी अनेक जीवनशैली-जनित बीमारियों को जन्म दिया है जो पहले दुर्लभ थीं। इन बीमारियों में सबसे बड़ी और भयावह बीमारी है-दिल का रोग। दिल की बीमारियाँ आज विश्व में असमय मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बन चुकी हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हाल ही में जारी कॉजेज ऑफ डेथ इन इंडिया 2021-23 की रिपोर्ट इस खतरे की गंभीरता को और स्पष्ट करती है। पहले जहाँ माना जाता था कि हृदय रोग और दिल के दौरे बुजुर्गों की बीमारी है, वहीं अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अब 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में हृदयाघात से होने वाली मौतें तेजी से बढ़ रही हैं। यानी युवाओं में दिल का दौरा अब असामान्य नहीं,बल्कि आम होता जा रहा है। यह न केवल चिकित्सा जगत के लिए चिंता का विषय है बल्कि समाज और परिवार के लिए भी गहरी चिंता का कारण है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार,2021 में हृदय रोगों के कारण विश्वभर में लगभग 1.8 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। यह आंकड़ा किसी भी अन्य बीमारी से कहीं अधिक है। अकेले भारत में प्रतिवर्ष लगभग 28 प्रतिशत मौतें हृदय रोगों से होती हैं। इसका अर्थ यह है कि हर चौथा भारतीय हृदयाघात या उससे जुड़ी बीमारी का शिकार होकर अकाल मृत्यु का सामना कर रहा है। शहरी क्षेत्रों में यह दर और भी अधिक है क्योंकि वहाँ तनाव, प्रदूषण, अस्वस्थ भोजन और व्यायाम की कमी का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कहीं ज्यादा है। विशेष चिंता की बात यह है कि भारत में 40 प्रतिशत से अधिक दिल के दौरे 40 वर्ष से कम आयु में आ रहे हैं। यह आंकड़ा अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों से कहीं अधिक है,जहाँ यह दर 10 से 15 प्रतिशत के बीच है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारतीय युवा पीढ़ी का हृदय पहले से कहीं अधिक असुरक्षित एवं खतरे में है। नमूना पंजीयन सर्वेक्षण के नए आंकड़े विशेषकर दिल के प्रति सजग रहने की वकालत करते हैं। भारत में सबसे अधिक करीब 31 फीसदी मौतें दिल की बीमारियों के कारण होती हैं। यदि हम यहां पर भारत में मोटापे की राष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो भारत में मोटापे की औसत दर लगभग 40.3 प्रतिशत है, जिसमें महिलाओं में यह दर 41.88 प्रतिशत और पुरुषों में 38.67 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में यह दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। आंकड़े बताते हैं कि पुडुचेरी, चंडीगढ़,और दिल्ली जैसे राज्यों में मोटापे की दर उच्चतम है। भारत में सबसे अधिक करीब 31 फीसदी मौतें दिल की बीमारियों के कारण होती हैं। सर्वेक्षण में यह पता चला है कि 30 से अधिक उम्र वाले लोगों में मौत की सबसे बड़ी वजह यही है। देश के 28 राज्यों और आठ केंद्रशासित क्षेत्रों में करीब 88 लाख लोगों पर किए गए इस सर्वेक्षण से यह पता लगाने की कोशिश की गई थी कि भारत में मौत की वजह क्या है और किस बीमारी से कितनी जान जा रही है? एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हुई। हालांकि,2022 और 2023 में स्थिति में सुधार देखा गया, लेकिन महामारी के प्रभाव से उत्पन्न स्वास्थ्य संकटों का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। दिल की बीमारियों की बढ़ती प्रवृत्ति को केवल चिकित्सा या आनुवंशिक कारणों से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे कई सामाजिक,आर्थिक और जीवनशैली संबंधी कारण हैं। आज का युवा वर्ग फास्ट फूड, जंक फूड और प्रोसेस्ड भोजन पर अधिक निर्भर है। इसमें उच्च मात्रा में तेल, नमक और चीनी होती है,जो हृदय की धमनियों को अवरुद्ध कर देती है। पारंपरिक संतुलित आहार जिसमें दाल,सब्जियां,अनाज और फल शामिल थे,अब जीवन से गायब होते जा रहे हैं। आधुनिक जीवन की दौड़-भाग,नौकरी और कैरियर की अनिश्चितता,प्रतिस्पर्धा,आर्थिक दबाव और सामाजिक अपेक्षाएँ युवाओं को लगातार मानसिक तनाव में रखती हैं। तनाव से हार्मोनल असंतुलन होता है और यह हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप को प्रभावित करता है। धूम्रपान, शराब और अन्य नशे की वस्तुएँ दिल की बीमारी के सबसे बड़े कारणों में शामिल हैं। धूम्रपान से रक्त नलिकाएँ सिकुड़ जाती हैं और धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यही स्थिति शराब और ड्रग्स से भी उत्पन्न होती है।

शहरी जीवनशैली ने युवाओं को गतिहीन बना दिया है। दिनभर दफ्तर या कंप्यूटर पर बैठकर काम करने से शारीरिक गतिविधियाँ नगण्य हो जाती हैं। मोटापा,ब्लड प्रेशर और डायबिटीज इसी निष्क्रिय जीवनशैली की उपज हैं और ये तीनों मिलकर दिल की बीमारी का बड़ा खतरा पैदा करते हैं। महानगरों की हवा में जहरीले कणों की बढ़ती मात्रा भी दिल की धड़कन और श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि प्रदूषण से हृदयाघात की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जिन परिवारों में पहले से दिल की बीमारियाँ रही हैं, उनमें यह जोखिम अधिक रहता है। लेकिन पहले केवल यही एक बड़ा कारण माना जाता था,जबकि अब जीवनशैली के कारक अधिक प्रभावी साबित हो रहे हैं। दिल की बीमारियाँ केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य की समस्या नहीं हैं,बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिणाम हैं। जब कोई 30 या 40 वर्ष का युवा अचानक दिल का शिकार होकर मर जाता है तो उसके परिवार की आर्थिक रीढ़ टूट जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ युवाओं को सबसे बड़ी पूंजी और शक्ति माना जाता है,वहाँ उनका इस प्रकार बीमार होना राष्ट्र के भविष्य को भी खतरे में डालता है। दिल की बीमारियों से बचाव संभव है,यदि समाज और व्यक्ति दोनों ही स्तर पर गंभीर प्रयास किए जाएँ। भोजन में ताजे फल,हरी सब्जियाँ, साबुत अनाज,दालें और कम वसा वाला भोजन शामिल किया जाए। नमक,चीनी और तैलीय भोजन का सेवन सीमित किया जाए। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट पैदल चलना, योग, प्राणायाम और हल्की कसरत को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। ध्यान,मेडिटेशन और समय प्रबंधन की आदतें तनाव को कम कर सकती हैं। धूम्रपान, शराब और अन्य नशों से दूर रहना हृदय को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी कुंजी है। ब्लड प्रेशर,शुगर और कोलेस्ट्रॉल की समय-समय पर जांच से बीमारी का प्रारंभिक चरण में पता लग सकता है। सरकार,सामाजिक संस्थाएँ और चिकित्सा जगत को मिलकर दिल की बीमारियों के प्रति जनजागरण अभियान चलाना चाहिए। दिल की बीमारी आज 'साइलेंट किलर' बन चुकी है। यह अचानक प्रकट होकर जीवन को समाप्त कर देती है। लेकिन यह पूरी तरह अनियंत्रित नहीं है। यदि हम अपने जीवन में अनुशासन,संतुलन और संयम को स्थान दें,तो हृदय रोग से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। कॉजेज ऑफ डेथ इन इंडिया 2021-23 की रिपोर्ट केवल एक चेतावनी है कि अब समय आ गया है जब समाज और व्यक्ति दोनों को इस खतरे को गंभीरता से लेना होगा। यह केवल चिकित्सकों या अस्पतालों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है कि वह अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए सजग और सतर्क रहे। दिल की धड़कनें जीवन का संगीत हैं,इन्हें समय से पहले मौन होने से बचाना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत की चिकित्सा स्थितियां एवं सेवाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जहां सुधर रही हैं,वहीं स्वास्थ्य-स्थितियां नई-नई चुनौतियां लेकर खड़ी हो जाती है। इसलिये चिकित्सा-स्थितियों के साथ-साथ स्वास्थ्य-स्थितियों में सुधार की तीव्रता से अपेक्षा है। भारत में स्वास्थ्य-क्रांति का शंखनाद हो,यह व्यक्तियों को स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करें,सरकारों को स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और संसाधनों में निवेश करने के लिए प्रेरित करें और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित करे।

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

हिन्दी का राष्ट्रभाषा न बन पाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य

आत्माराम यादव
नर्मदापुरम,मध्यप्रदेश

देवनागरी लिपि हिन्दी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई ओर भारतीय संविधान में राष्ट्र का तो उल्लेख है किन्तु राष्ट्र भाषा का उल्लेख न होना गंभीर चिंतन का विषय है जबकि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा देने वाले लोकमान्य गंगाधर तिलक ने देशवासियों से अपील करते हुये कहा था कि यदि आप किसी राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना चाहते है तो सबके लिए समान भाषा से बढ़े कर तया सशक्त अन्य कोई बल नहीं है। तिलक कि मान्यता थी कि हिन्दी ही एकमात्र भाषा है जो राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी है इसलिए वे देवनागरी को राष्ट्रलिपि ओर हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानते थे। उनका मानना था कि राष्ट्र संगठन के लिये आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सकता है। हिन्दी राष्ट्र भाषा बन सकती है, यह आग्रह अकेले तिलक जैसे नेताओं ने ही नहीं अपितु दक्षिण भारत के नेताओं ने भी किया ओर हिन्दी का तिलक काश्मीर से केरला तक विभूषित करना चाहा था पर हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के लिए विरोध भी था,परिणामस्वरूप 14 सितंबर 1949 को हिन्दी राजभाषा बनकर ही सीमित रह गई। भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 7 1 7 के तहत देश मे देवनागरी लिपि को राजभाषा का दर्जा दिया गया है पर उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नही मिल सका, यह देवनागरी लिपि हिन्दी के लिए सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं है तो क्या है?

महात्मा गांधी देश भ्रमण पर जब भी किसी भी प्रदेश या नगर में जाया करते तो वहाँ हर आम व्यक्ति से लेकर विशेष व्यक्ति तक के द्वारा सबसे ज्यादा हिन्दी भाषा का प्रयोग आमबोलचाल में होता था तभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा ओर पहली बार मध्यप्रदेश कि धरती अहिल्या कि नगरी इन्दौर में वर्ष - 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कर सभी का दिल जीत लिया। अकेले गांधी ही नहीं राजर्षि टंडन सहित,जवाहरलाल नेहरू भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे ओर वर्ष 1946-1949 तक संविधान बनाने ओर उसपर लंबी बहस चलती रही किन्तु संविधान किस भाषा में लिखा जाना है ओर किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया जाए यह मामला उलझ कर रह गया ओर संविधान समिति एक मत पर सहमत नही हुये जिससे राष्ट्रभाषा हिन्दी का मामला कठिनाई में आ गया ओर हिन्दी राजभाषा तक ही सीमित रह गई, यह अलग बात है कि सरकार ने

राजभाषा को लेकर कानून बनाकर संतुष्ट करने का प्रयास किया। चूंकि उस समय देश का विभाजन सबसे बड़ा कारण था जो हिन्दी को सर्वोच्च स्थान देने कि बजाय उर्दू कि बात भी शामिल कि गई पर बटवारे कि इस खाई ने हिन्दी से उसका अधिकार छीन लिया ओर तत्समय के नेता संतुष्टिकरण कर हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने में पीछे हट गए।

स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित किए जाने हेतु महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत हिन्दी के बहूतेरे समालोचक भारत की अन्य सभी प्रादेशीय उन्नत भाषाओं और भारत की गुलामी की प्रतीक रही आंग्ल इंग्लिश भाषाओं से हिन्दी की तुलना करते समय हिन्दी को बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। इसपर कुछ लोग उन्हें कोसते हैं,और कुछ लोग उन्हें अनभिज्ञ भी कह सकते है, पर सच तो यह है कि किसी का मुंह कोई बन्द नहीं कर सकता। जिसे आलोचना करना है वह उसकी आदत है, वह आदत नहीं छोड़ेगा। यहाँ वोटों की गंदी राजनीति करने वाले नेताओं के ललाट पर चन्दन का तिलक है, पैर में पीब-भरा घाव है। अगर मक्खी चन्दन के टीके पर न बैठकर स्वभावतः घाव पर जा बैठे, तो क्या आप उस मक्खी को इसलिए मार डालेंगे, कि वह कम्बख्त चन्दन के टीके पर क्यों न बैठी? कुछ इसी प्रकार का कार्य व्यवहार हिन्दी को मातृभाषा मानने वाले तथा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राष्ट्रभाषा का दर्जा न दिलाने वालों ने किया है। देश आजाद हुआ उस समय हिन्दी साहित्य जगत के एक से एक मूर्धन्य साहित्यकार,लेखक थे,संसद में उनकी उपस्थिती थी किन्तु वे हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सम्मान न दिला सके ओर अनेकों ने तो राष्ट्रीय पुरुस्कार सरकार को लौटा दिये, किन्तु वे हिन्दी के सौभाग्य के दिन वापिस नहीं ला सके ओर आज देश को आजाद हुये 78 वर्ष हो गए किन्तु हम देवनागरी लिपि हिन्दी का सम्मान कितना करते है यह वही बात हुई कि चंदामामा चाहने वाले बच्चे के रूठने पर उसे पानी की थाली में चंदामामा देकर खुश कर दिया जाता है ठीक हम भी आज हिन्दी साहित्य के सारे सपूत हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सम्मान तो दिला न सके बस बच्चे कि तरह हर साल हिन्दी दिवस पर हिन्दी सजा राजभाषा दिलाये जाने पर ही खुश है, कभी पुरूषार्थ नहीं किया कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिला सके। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को 1963 में भारत सरकार ने पद्मभूषण से अलंकृत किया था किन्तु जैसे ही राष्ट्रभाषा हिन्दी पर आघात करने वाले राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में उन्होने देवनागरी हिन्दी को सम्मान देते हुये यह पद्मभूषण अलंकृत सरकार को लौटा दिया, यह वह दौर था जब उन जैसे अनेक राष्ट्र कवि,लेखक साहित्यकार आदि ने भी अपने को मिले सारे सरकारी पूस्कार अपनी कलम-कुदाल के साथ हिन्दी विरोधी नेताओं की अंगेजी भाषा के प्रति अनचाही तृष्णा को भेंट कर हिन्दी- संसार के सभी गड्ढों को भर देने का काम उसी प्रकार किया जैसे हाल ही में डेंगू फैलानेवाले मच्छर युद्धस्तर पर अपने काम में लगे रहकर सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़े है ओर इन डेंगूओ की शिकार जनता डेंगू से मुक्ति हेतु अस्पतालों में कतार में खड़ी है। हिन्दी दिवस मनाए जाने पर मेरे मन में विचार आता है कि आज हमारे आधुनिक साहित्य के अधिकांश समीक्षक अपनी पूर्व पीढ़ी से सबक क्यों नही लेती । ज्यादा तंज! हिंदी विभाग में शोध का असली रणक्षेत्र वह कार्यालय-कक्ष होता है,जहां पंखा उतनी बार नहीं चलता जितनी बार गाइड की तपस्या सुनाई जाती है। आप शोध शुरू करो तो सबसे पहले गाइड साहब को खोजो। गाइड वही है, जो तीन दिन में रिसर्चर को तीन बार अभी बहुत काम बाकी है कह सके, और चौथे दिन अपने कुत्ते को घुमाते हुए शोध मौलिक हो! का मंत्र दे जाए। गाइड की खोली में बैठे-बैठे चाय बनाओ,पालतू बिल्ली से दोस्ती करो, और हर शाम उसकी छत पर किसी न किसी विभागीय बोधगाथा का प्रसारण सुनो। रिसर्चर बेचारा बाहर से आया बिरयानी खाने, लेकिन गाइड हर दिन भूखे पेट ही लौटा देता है। किताबों का मिलना वैसी ही टेढ़ी खीर है,जैसे विश्वविद्यालय के क्लर्क से सही फाइल नंबर मिलना। बुक डिपो वालों से महीने भर मांगो,लाइब्रेरी वाले शर्मा जी को घुटने छुओ, तब कहीं जाके 'आधुनिक हिंदी काव्य पर शोध' की पुरानी फटी किताब हाथ लगे। पुराने शोधार्थियों के पास संदर्भग्रंथ वैसे गिरवी पड़े रहते हैं जैसे मंहगाई में गहने। अगर कोई किताब मिल भी जाए तो ताज्जुब नहीं–उस पर गाइड या उसकी बीवी का नाम खुदा होगा और पन्नों के बीच लाइब्रेरी की रसीद की जगह पान की पुड़िया दबी मिलेगी! विषय चुनने का पाखंड भी दिलचस्प है।

डॉ. साहब,क्या आपने भी पापड़ बेले हैं?

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा

कल अखबार की पहली खबर ने तो पूरे हिंदी विभाग को ऐसा हिला दिया जैसे गर्मी में विभागाध्यक्ष के कमरे में एसी की हवा घुस जाए! ÷प्रोफेसर डॉ. सत्यपाल भटनागर तीन हफ्ते के अमरीकी दौरे पर जा रहे हैं - विषय 'भारतीय संस्कृति में हिंदी', साथ में शोध-प्रबंध भी पढ़ेंगे। यह पढ़ते ही निचले विभागकक्ष में चाय पिलाने वाले चपरासी तक की छाती फूल गई - इत्ती बड़ी खबर! हिंदी में नाम हुआ कि विदेश जाना, वरना तो प्रायोगिक हिंदी अध्यापक का हाल वही रहता है, जो सरकारी स्कूल में अंग्रेजी शिक्षकों का हाजिरी पूरी,काम आधा,नाम लुस। पर हिंदी के डॉ. भटनागर यथार्थ के मीटर-ऐरे-गैरे-नत्थू खैरे से दिल नहीं लगाते, वे शोध की चौपाल लगाने और छात्रों के भविष्य का 'प्रोजेक्शन' बनाने में विश्वास रखते हैं।

सुना था,शोध वही करता है, जिसे दुनिया की कोई भी और नौकरी नहीं मिलती! खुद डॉ. भटनागर भी तो कभी विभाग में चकमा मारते हुए रिसर्चर बन गए। रिसर्चर बनने के बाद तो जैसे कलाई पर मुफ्त की घड़ी मिल गई घंटियाँ सिर्फ विभागाध्यक्ष के दरवाजे से टकराती रहती हैं। बाकी–शोध के लिए लाइब्रेरी का समय,विभाग के बाबुओं की मुस्कान, और सहपाठियों का भ्रष्टाचार सब बेमतलब! असली मजा तो तब आता है,जब शोधार्थी के हाथ में 'थीसिस जमा' की पावती होती है और मुँह में उपाध्याय जी की चायकम चीनी,

चुनौतियों के बीच शिक्षक

विजय गर्ग
मलोट,पंजाब

भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में गढ़ा जा रहा है । सार्वभौमिक प्रतीत होती इस पंक्ति के साथ कोठारी आयोग ने अपनी विस्तृत रपट 1964 में लिखी और शायद ही सोचा होगा कि इसके छह दशक बाद भी यह भविष्य उन कक्षाओं में रचा जा रहा होगा, जहां मार्गदर्शन के लिए अध्यापक की बाट देखी जा रही है। आज बढ़ती संख्या वाली कक्षाएं अपनी और राष्ट्र की तकदीर लिखने को तैयार बैठी हैं, लेकिन उनमें वह अभिप्रेरणा नहीं है, जो शिक्षक की उपस्थिति से आती है। शिक्षक, जिसे भविष्य गढ़ने का शिल्पी कहा गया,इन कक्षाओं में कम होते जा रहे हैं। परिणाम यह है कि लाखों बच्चे बिना किसी मार्गदर्शन के अपनी किस्मत और देश का भविष्य अंधेरे में गढ़ने को विवश हैं।

हाल ही में आई एक खबर में यह दावा किया गया कि भारत में एक करोड़ शिक्षक चौबीस करोड़ बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। यह अनुपात शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिहाज से आदर्श है, लेकिन जमीनी हकीकत उतनी अच्छी नहीं दिखती। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश,तमिलनाडु,राजस्थान,कर्नाटक,गुजरात और आंध्र प्रदेश-ये दस राज्य देश की कुल आबादी का लगभग सत्तर फीसद हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज आंकड़े दर्शाते हैं कि पूरे प्रदेश में 1,32,855 सरकारी स्कूलों को 6,03,441 शिक्षक संभाल रहे हैं। औसतन देखें तो हर स्कूल में 4.5 शिक्षक नियुक्त हैं। यहीं से असमानता की असली तस्वीर सामने आती है। इन्हीं आंकड़ों में यह भी दर्ज है कि 8,866 स्कूल ऐसे हैं, जहां सिर्फ एक शिक्षक तैनात है और इन स्कूलों में 6,11,950 बच्चे पढ़ते हैं। यानी एक शिक्षक को औसतन उनहत्तर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की तरह ही अन्य नौ सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों की स्थिति भी चिंताजनक है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि कुल 10,17,660 सरकारी स्कूलों में से 1,10,971 स्कूल ऐसे हैं, जहां पूरे विद्यालय की बागडोर केवल एक ही शिक्षक के हाथ में है । शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं। यह कहावत आज की हकीकत में कितनी बेमानी लगती है, जब देश के सरकारी स्कूलों में लाखों शिक्षकों की कमी है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक,देश में लगभग दस लाख शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है,जिनमें से चार लाख शिक्षकों की जरूरत तो केवल प्राथमिक स्तर पर ही है। हालांकि,संख्या के हिसाब से यह कोई असंभव कार्य नहीं है। ठोस कदम उठाए जाएं, तो एक वर्ष के भीतर ही इन रिक्तियों को भरा जा सकता है। मगर यह न केवल शिक्षण के पेशे के प्रति उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के प्रति उपेक्षा भी करता है। भले ही भारत सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) का हस्ताक्षरकर्ता है, पर पिछले एक दशक से शिक्षक भर्ती और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम लगातार अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर बार कुछ वर्ष में ही शिक्षक और शिक्षा पाठ्यक्रम बिना किसी स्पष्ट दृष्टि के लगातार बनाए और बदले जाते रहे हैं। नीति-निर्माताओं की अटपटी योजनाओं के चलते आज भी इस पर स्पष्टता नहीं है कि एक व्यक्ति को बेहतर शिक्षक बनने के लिए किस तरह की शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र में सेवा की स्थिति और वेतनमान की समस्या आज गंभीर होती जा रही है और इसके निदान के संकेत नहीं मिल रहे । 7 भर्ती प्रक्रिया की अनवरत देरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी शिक्षण पेशे को अरुचिकर बनाती जा रही है। नतीजतन, प्रतिभाशाली और योग्य युवा इस क्षेत्र में आने से कतराते हैं। सवाल है कि जब भविष्य गढ़ने वाले स्वयं ही असुरक्षा और आर्थिक असमानता से जूझ रहे हों, तो शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों का भविष्य किस आधार पर सुरक्षित माना जाए ? शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर लिए गए नीतिगत निर्णय स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पेशेवर मानकों (एनपीएसटी) और हर वर्ष पचास घंटे की अनिवार्य सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) जैसी पहल शिक्षण को सशक्त बनाने के बजाय बोझिल बना रही हैं। ये कदम अतिरिक्त नौकरशाही बोझ बनकर उभर रहे हैं, जो उनकी स्वायत्तता को कमजोर करते हुए मनोबल गिरा रहे हैं। नीतिगत विफलताओं का बोझ सीधे शिक्षकों के कंधों पर डालने से पहले यह जरूरी है कि नीतियों पर फिर से सोच-विचार किया जाए। कागजों में शिक्षकों की तुलना गोविंद से करने की भावपूर्ण भाषा का सहारा लेने के बजाय उन्हें वास्तविक सम्मान,गरिमा और पेशेवर स्वायत्तता मिले। जब तक शिक्षा प्रणाली में ऐसे मौलिक बदलाव नहीं होंगे,तब तक शिक्षक महज आज्ञाकारी वेतनभोगी कर्मचारी बनकर रहेंगे और अपने नियंताओं की वैचारिक प्राथमिकताओं और आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। इक्कीसवीं सदी में शिक्षक होना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदार कर्तव्य बन चुका है।

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

C M Y K

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का शक्तिप्रदर्शन,सरगुजा में प्रदेशाध्यक्ष व विकास मरकाम का ऐतिहासिक स्वागत

ढोल-नगाड़ों और नारों के बीच सरगुजा में उमड़ा जनसैलाब,सत्यनारायण सिंह व मरकाम का भव्य अभिनंदन

-संवाददाता-
अंबिकापुर,12 सितम्बर 2025 (घटती-घटना)।
भाजपा अनुसूचित अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम के प्रथम सरगुजा आगमन पर संभाग स्तरीय बैठक सह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जगह-जगह उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। गत मंगलवार को यह स्वागत का कार्यक्रम तारा से शुरू होकर उदयपुर, लखनपुर, मेंड्राकला चौक,बिलासपुर चौक,महामाया चौक,संगम चौक,घड़ी चौक,गांधी चौक, अंबेडकर चौक होते हुए पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में उद्बोधन सह मंचीय कार्यक्रम के साथ में संपन्न हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा एवं संभाग भर से आए हुए जनजाति समुदाय के नृत्य समूहों के द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान हजारों की संख्या में जनजाति लोग सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर की सड़कों पर दिखाई दिए।ढोल नगाड़ों की झंकार से आकाश गुंजायमान रहा एवं जनजाति मोर्चा जिंदाबाद, धरती माता की जय,भारत माता की जय ऐसे नारे गूंजते रहे। इसके पश्चात पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित सभा में स्वागत उद्बोधन में जिला सरगुजा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष धन राम नागेश ने इस अवसर पर पधारे समस्त अतिथियों का स्वागत किया एवं आने वाले समय में नवगठित होने वाले संगठन में अच्छा काम करने हेतु कार्यकर्ताओं को अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर भाजपा सरगुजा के जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा की सरकार बनाने में जनजाति मोर्चा की बड़ी भूमिका रही है सरगुजा संभाग जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है यहां बड़ी संख्या में जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं जिनको भाजपा की विचारधारा से जोड़ने का काम जनजाति मोर्चा ने किया है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जनजाति सीट जीतने में भाजपा सफल रही है और आने वाले समय में भी जनजाति मोर्चा भाजपा की सरकार फिर से बनाने में सक्षम है उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम का भी सरगुजा की धरती पर प्रथम आगमन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन प्रेषित किया। इस अवसर पर औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा की जनजाति मोर्चा आज धरातल पर मजबूत हुआ है और लगातार भाजपा से प्रभावित होकर भाजपा के विचारधारा से जुड़ रहा है भाजपा ने जनजातीयों को उचित सम्मान देने का काम किया एक जनजाति को राष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर सुशोभित किया साथ ही उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जनजाति सीएम बनाकर उनको नेतृत्व करने का मौका प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जो देश के लिए काम करती है और सभी वर्गों का उचित सम्मान करते हुए उनके विकास के लिए काम करती है आने वाले समय में भी जनजाति मोर्चा अपना दमखम दिखाते हुए जनजातियों के बीच में बहुत ही सक्रियता से काम करते हुए सरकार की योजनाओं का उचित लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगा। इस अवसर पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तो यही कहानी रही है की जो सरगुजा एवं बस्तर जीत लेता है सरकार उसी की बनती है सरगुजा संभाग में जनता ने बड़ी संख्या में विधानसभा सीट भाजपा को प्रदान की है साथ ही बस्तर का भी पूर्ण सहयोग मिला है। सरगुजा संभाग में तो पाने के लिए कुछ बचा नहीं है यहां हमारे जनजाति समुदाय से विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष यहां तक की नगर निगमों में भी हमारे जनप्रतिनिधि विराजमान हैं आने वाले समय में केवल इस बढ़त को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है लेकिन जनजाति मोर्चा सरकार की सभी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगा साथ ही जनजाति समाज के उत्थान के लिए कार्य करेगा और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा इस दौरान उन्होंने अपने इस अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक स्वागत के लिए संभाग के सभी कार्यकर्ता एवं भाजपा संगठन का धन्यवाद किया। इस दौरान अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ देवेंद्र माहला, एमडी ठाकुर, प्रदेश मंत्री एवं सरगुजा संभाग प्रभारी अनुज एक्का महापौर मंजूषा भगत, जिला पंचायत सरगुजा अध्यक्ष निरूपा सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर हीरामनी निकुंज, जिला पंचायत अध्यक्ष सूरजपुर चंद्रमणि पैकरा, फुलेश्वरी पैकरा, कुसुम सिंह, बंसीधर उरांव, आशु पोडेटी,अंकित तिर्की, अजय श्याम, बिहारीलाल उरांव, जयंत मिंज, हीरा सिंह टेकाम, कौशल सिंह, रामप्रताप सिंह, ललित नागेश, शिवशंकर सिंह, उजीत नारायण सिंह पूरन टेकाम, कमलेश टोप्पो, राजा चावर, सेतराम बड़ा, अनिल निराला, अभिषेक पावले, अनामिका पैकरा, शशिकला भगत, ललिता तिर्की सहित बड़ी संख्या में जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे ।

एसपी ने ली जनरल परेड की सलामी उत्कृष्ट प्रदर्शन पर किया सम्मानित

-संवाददाता-
अंबिकापुर,12 सितम्बर 2025 (घटती-घटना)।

रक्षित केंद्र अंबिकापुर में शुक्रवार को आयोजित जनरल परेड की सलामी एसपी राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा ली गई। परेड निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिस अधिकारियों एवं जवानों की वेशभूषा (टर्नआउट) का अवलोकन कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को इनाम देकर प्रोत्साहित किया। जनरल परेड के दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों की टोली बनाकर अनुशासित रूप में परेड कराई गई। सुसज्जित पुलिस बैंड की मधुर धुन पर परेड का आयोजन हुआ,जिसे लेकर एसपी ने आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। परेड उपरांत एसपी राजेश ने वाहन शाखा,शस्त्रागार,स्टोर शाखा का निरीक्षण कर शासकीय वाहनों एवं शस्त्रों के रखरखाव और रिकार्ड संधारण पर विशेष जोर दिया। साथ ही उन्होंने पुलिस कल्याण कैन्टीन एवं पुलिस बैंक का अवलोकन कर कर्मचारियों को इन सुविधाओं का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो,सीएसपी राहुल बंसल,रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत, सहित कुल 134 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सर्पदंश से पीड़ित महिला की मौत

-संवाददाता-
अंबिकापुर,12 सितम्बर 2025 (घटती-घटना)।
सर्पदंश से पीड़ित महिला की 9वें दिन रायपुर ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम तुरियाबीरा की बविया यादव पति जमुना यादव 37 वर्ष, बीते 3 सितम्बर को धान का फसल देखने के लिए खेत की ओर जा रही थी। रास्ते में मेड़ पर महिला को पैर में जहरीला सांप डस लिया। इसकी जानकारी मिलने पर स्वजन उसे बरगीडीह स्वास्थ्य केन्द्र ले गए, यहां से रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे थे। पीड़ित महिला को आवश्यक उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। स्थिति में सुधार नहीं होने पर बेहतर इलाज के लिए गुरूवार को हायर सेंटर रायपुर रेफर किया गया था।

रजत जयंती के अवसर पर शासकीय महाविद्यालय राजपुर में भूतपूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया

-संवाददाता-
राजपुर,12 सितम्बर 2025 (घटती-घटना)।
बलरामपुर जिले के शासकीय महाविद्यालय राजपुर में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार, 12 नवंबर को भूतपूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन पूर्व छात्रों, शिक्षकों और वर्तमान विद्यार्थियों के बीच आपसी संवाद, अनुभव साझा करने तथा महाविद्यालय की प्रगति पर विचार-विमर्श का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना एवं छत्तीसगढ़ राज्यगीत से हुई। इसके पश्चात स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। मंच संचालन मनोज खलखो ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. जीतन राम पैंकरा ने

कहा कि महाविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं,बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का माध्यम भी है। उन्होंने विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ-साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी तैयार रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने 2027 में होने वाले नैक मूल्यांकन में महाविद्यालय को ए ग्रेड दिलाने के सामूहिक प्रयास की बात कही। नई शिक्षा नीति पर वक्तव्य देते हुए नोडल ओमप्रकाश गुप्ता ने नई शिक्षा नीति की विशेषताओं और महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह नीति विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा, शोध व नवाचार की दिशा में प्रोत्साहित करेगी तथा स्थानीय स्तर पर भी नए अवसर प्रदान करेगी। प्राध्यापक डॉ. अंजना टोप्पो ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन में छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और महाविद्यालय को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। पूर्व छात्र एवं राजपुर जनपद अध्यक्ष आकाश अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद महाविद्यालय ने समय-समय पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने ड्रेस कोड व्यवस्था और अनुशासन को सराहनीय बताते हुए सभी पूर्व छात्रों से अपील की कि वे महाविद्यालय से जुड़े रहकर इसके निरंतर विकास में योगदान दें। रजत जयंती समारोह का यह पूर्व छात्र सम्मेलन न केवल स्मृतियों को ताज़ा करने का अवसर रहा, बल्कि महाविद्यालय के भविष्य के लिए प्रेरणा और ऊर्जा देने वाला भी सिद्ध हुआ। समारोह में महाविद्यालय के स्टाफ,विद्यार्थी और भूतपूर्व छात्र छात्राएं उपस्थि रहे।

काम करते वक्त गिरकर घायल हुए राजमिस्त्री की मौत

-संवाददाता-
अंबिकापुर,12 सितम्बर 2025 (घटती-घटना)।
प्लास्टर करते समय गिरने से घायल राजमिस्त्री की मौत हो गई। घटना उदयपुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया ग्राम लक्ष्मणगढ़ के डांगपारा का समुद्र साय पिता घासी मझवार 45 वर्ष,राजमिस्त्री का काम करता था। वह गांव में ही प्यारेलाल के यहां धनेश्वर के साथ मजदूरी करने गया था। काम करने के दौरान वह अचानक अनियंत्रित होकर गिर गया। घायल अवस्था में राजमिस्त्री को उदयपुर स्वस्थ्य केन्द्र लाया गया,यहां से रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लाया गया,यहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने स्वजन के मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है।

मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण शुरू व्यवसाय के रूप में अपनाने पर जोर

-संवाददाता-
अंबिकापुर,12 सितम्बर 2025 (घटती-घटना)।
कृषि विज्ञान केन्द्र अंबिकापुर में मधुमक्खी पालन पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 8 सितंबर से की गई है। यह कार्यक्रम नेशनल बीकीपिंग एवं हनी मिशन के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को राजमोहिनी देवी कृषि विद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, अंबिकापुर का शैक्षिक भ्रमण कराया गया। वहां उन्हें मधुमक्खियों की विभिन्न प्रजातियों की पहचान, पालन के दौरान सावधानियां, तथा शहद प्रसंस्करण इकाई के कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। प्रसंस्करण तकनीक से शहद की नमी 25-30% से घटाकर 17% की जाती है।

पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत साइबर सेल की मदद से अपहृत नाबालिक बालिका को किया बरामद,आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा सलाखों के अंदर

-संवाददाता-
शंकरगढ़,12 सितम्बर 2025 (घटती-घटना)।
मामला बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र का है। आरोपी- पंकज लकड़ा पिता प्रभु लकड़ा उम्र 30 वर्ष पता डोंगरो थाना चलगली,जिला बलरामपुर रा गंज ने एक नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकरअपने साथ ले गया था। प्राथिया के शिकायत पर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत साइबर सेल के मदद से पुलिस ने अपहृत बालिका को बरामद कर आरोपी को भेजा सलाखों के अंदर। जानकारी के अनुसार प्रार्थीया ने दिनांक 10.09.2025 को थाना शंकरगढ़ थाने में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि

उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की दिनांक 04/09/ 2025 की सुबह करीब 5:00 बजे बिना बताए कहीं चली गई है। आस-पड़ोस रिश्तेदारों में पता करने के वाऊजूद कहीं पता नहीं चला। प्राथिया के द्वारा पुलिस को अपने आवेदन में उल्लेखित करबताया की उसकी नाबालिक लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बाहला फुसला कर कहीं भगाकर ले गया है। पुलिस ने प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना शंकरगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर. अपराध क्रमांक- 125 /2025, धारा- 137(2)भारतीय न्याय संहिता जोड़ने धारा 87,64 भारतीय न्याय संहिता धारा 4,6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया ।

छात्राओं को साइबर अपराध,विधिक अधिकार और सुरक्षा की दी गई जानकारी

पुलिस द्वारा कन्या विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

-संवाददाता-
अंबिकापुर,12 सितम्बर 2025 (घटती-घटना)।
एसपी राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में छात्राओं को विधिक अधिकारों, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लगातार स्कूल-कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर में साइबर एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य आरएल मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के युग में साइबर सुरक्षा और विधिक जानकारी छात्राओं के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में उप निरीक्षक अभय तिवारी ने छात्राओं को यातायात नियमों,सडक़ सुरक्षा, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सडक़ सुरक्षा केवल कानून पालन नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा की गारंटी है। साइबर सेल के विशेषज्ञ अनुज जायसवाल ने छात्राओं को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, ओटीपी शेयरिंग, डिजिटल फ्रॉड,ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क रहने के उपाय बताए। अंत में सभी छात्राओं को सजग नागरिक बनने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान साइबर सेल प्रभारी एएसआई अजीत मिश्रा,शिक्षिका सुनीता दास,पुलिस मितान,साइबर वॉलंटियर टीम एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

न्यायालय नजूल अधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक:, 202509021200045/0

विषय-अ-20(3) मामले की श्रेणी-राजस्व सन :- 2024-25

अम्बिकापुर प.ह.नं.00015 (हे.)]
पक्षकारों का विवरण:-
आवेदक पक्षकार-रजत कु0 बौरी,
अनावेदक पक्षकार-रंजीता बौरी

ईश्तहार

आवेदन रजत कुमार बौरी आ0 स्व0 कृष्ण कुमार बौरी निवासी बौरीपारा अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा सीट नम्बर-3 मोहल्ला देवीगंज रोड नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1165/15 रकबा 140 वर्गफीट भूमि को अपनी पत्नी अनावेदिका श्रीमती रंजीता बौरी पति रजत बोरी निवासी बोरीपारा अम्बिकापुर, थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के पक्ष में दान करने की अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उक्त संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपना लिखित आपित्त स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 26/9/2025 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 11/09/2025 को जारी किया जाता है।

सील
नजूल अधिकारी
अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अंबिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक:, 202509020700103

विषय-अ-6 मामले की श्रेणी-राजस्व सन :- 2024-25

फुन्दुरडिहारी प.ह.नं.00016
[392/4(0.020 0हे.)]
पक्षकारों का विवरण:-
आवेदक पक्षकार-दीपक कु0सिन्हा,
अनावेदक पक्षकार-सत्यभामा देवी

ईश्तहार

आवेदक दीपक कुमार सिन्हा आ0स्व0 कामता प्रसाद सिन्हा निवासी गोधनपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0म0 के द्वारा ग्राम फुन्दुरडिहारी स्थित भूमि खसरा नंबर 392/4 रकबा 0.020 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो से स्व0 सत्यभामा देवी का नाम विलोपित कर फोती नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है।
उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 29/09/2025 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 09/09/2025 को जारी किया जाता है।

सील
उमेश्वर सिंह बाज
तहसीलदार
अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अंबिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक:, 202509020700057

विषय-ब-121 मामले की श्रेणी-राजस्व सन :- 2024-25

कोलडिहा प.ह.नं.00053 (हे.)]
पक्षकारों का विवरण:-
आवेदक पक्षकार-सत्यनारायण,
अनावेदक पक्षकार-छ0ग0शासन,

ईश्तहार

आवेदक सत्यनारायण पिता गेदा, निवासी ग्राम कोलडिहा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम कोलडिहा स्थित खसरा नंबर 122/2 रकबा 0 203 है। भूमि के राजस्व अभिलेखों में त्रुटिवश रकबा 0.023 हे अंकित हो गया है. जबकि वास्तविक रकबा 0.203 हे0 है। आवेदक द्वारा उक्त त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है जो जाँच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।
उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 24/09/2025 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 04/09/2025 को जारी किया जाता है।

सील
उमेश्वर सिंह बाज
तहसीलदार
अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ

रा0प्र0क्र0 202509020700113 /अ-27/2024-25

फर्द बटवारा का अंतिम प्रकाशन

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के रा0प्र0क्र0 202509020700113/ अ-27 / 2024-25 पक्षकार बलजीत राजवाडे प्रति विश्वनाथ राजवाडे वगै, में ग्राम नवाबांध स्थित खसरा नंबर 88, 89/2, 92/1, 354/2, 361/2, 402/2, 404/1, 426/1 रकबा 0.032, 0.033, 0.024, 0. 368, 0.191, 0.271, 0.052, 0.273 हे. कुल खसरा नंबर 08 कुल रकबा 1.244 हे. भूमि का फर्द बंटवारा सूची हल्का पटवारी से प्राप्त हुआ है, जिसका अंतिम प्रकाशन कराया जा रहा है। अतः उक्त फर्द बंटवारा में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 22/09/2025 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
आज दिनांक 11/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा

सील
तहसीलदार
अम्बिकापुर,सरगुजा

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर,जिला-सरगुजा(छ0ग0)

ईश्तहार

धौरपुर,दिनांक 10/09/2025
क्रमांक/818/ खाद्य / अ0वि0अ0 / 2025 - एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ससौली के शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन संलग्नीकरण के माध्यम से शा0उ0मू0दुकान जामडीह द्वारा किया जा रहा है।
अतः ग्राम पंचायत ससौली के उचित मुल्य दुकान के संचालन हेतु इच्छुक एजेंसी जो छ0ग0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत संचालन हेतु पात्र हैं, वे अपना आवेदन पत्र विहित प्रारूप में सम्पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज यथा पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रस्ताव, कार्यवाही पंजी, बैंक पास बुक की सत्यापित छायाप्रति के साथ आवेदन दिनांक 25/09/2025 तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) धौरपुर में जमा कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 10/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी ।

(जे0आर0सतरंज)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धौरपुर,सरगुजा

जी0नं0-252603425/2

CMYK

चार मंत्री व मुख्यमंत्री वाले संभाग में सड़कों की स्थिति सबसे खराब क्यों?

सरगुजा संभाग में पांच मंत्री होने के बावजूद सड़को की स्थिति सबसे खराब

- अम्बिकापुर राजपुर मार्ग की हालत भी बद से बदतर आये दिन हो रही दुर्घटनाएं
- भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के नेता कर चुके विरोध पर सड़क की हालत वही

-राजन पाण्डेय-

अम्बिकापुर/कोरिया,12 सितम्बर 2025 (घटती-घटना)।

सरगुजा की सबसे व्यस्ततम मार्ग नेशनल हाईवे 43 की स्थिति पिछले कई सालों से जर्जर बनी हुई है। सरकारें आई और सरकारें गई, इस रोड को लेकर खूब राजनीति भी हुई,लेकिन राहगीरों का की समस्या का समाधान किसी ने नही निकाला, वर्तमान सरकार में छत्तीसगढ़ राज्य को मुख्यमंत्री सहित चार मंत्री देने वाला सरगुजा सम्भाग सड़को पर बने बड़े बड़े गड्ढों के लिए खुद को कोस रहा है। पिछली सरकार में उपमुख्यमंत्री सहित तमाम विधायक सत्ता पक्ष के होने के बावजूद सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नही थी,अम्बिकापुर एम जी रोड की हालत खराब थी, इसके बाद जनता ने नई उम्मीद के साथ सरकार बदल दी कि इस बार इन सभी समस्याओं से निजात मिल सकेगा नई सरकार में सरगुजा सम्भाग को पांच पांच मंत्री मिल गए और सभी विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायक सत्ता सीन हुए,जनता ने और प्यार बरसाया और सरगुजा की लोकसभा की सीट भी सत्ता पक्ष को सौंपी लेकिन शायद जनता के किस्मत में सड़कों को लेकर और परेशानी झेलना लिखा था नई सरकार में सड़कों की स्थिति और खराब हो गई पुराने गड्ढे बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो गए, और नए गड्ढे भी बन गए जिससे बारिश के कारण सड़के गड्ढों के साथ तालाब में बदल गई जिससे लोग दुर्घटना का शिकार होने लगे,लेकिन सरकार है कि सुन नही रही,अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ नेशनल हाईवे-43 की दुर्दशा से स्थानीय लोग परेशान हैं। सडक पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। गर्मी में उड़ रही धूल से लोग परेशान थे। राहगीरों के राहत के उद्देश्य से सडक पर बने गड्ढों में स्टोन डस्ट डालकर भरा गया था। जिससे भारी वाहनों के गुजरने के बाद उड़ रही धूल के गुबार से राहगीरों की परेशानी और बढ़ गई है। उड़ रही धूल के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने शुरू हो गई थी वही बारिश के दिनों में कीचड़ व सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से चलना मुश्किल हो गया था।

बेहतर सरकार चुनने के बाद भी गड्ढ़ों से पटे पड़े सड़क पर आवागमन करने की मजबूरी क्यों?

एनएच-43 अंबिकापुर शहर के बीचो बीच होते हुए निकली है। जो सूरजपुर जिले को जोड़ती है। सदर रोड, देवीगंज रोड से लेकर रेलवे स्टेशन तक की सड़क पिछले तीन से चार सालों से खराब है। अच्छी सड़क की उम्मीद को लेकर लोगों ने प्रदेश में सरकार भी बदल दी। इसके बावजूद भी स्थानीय लोगों को अच्छी सड़क नसीब नहीं हुई। वही गड्ढों से पटे पड़े सड़क पर आवागमन करने को लेकर मजबूर हैं। दिनों दिन सड़क पर गड्ढों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। गाड़ियां खराब हो रही है। लोगों की जाने जा रही है पर इसे जिम्मेदारों का लेना देना कुछ नहीं है। सड़क की दुर्दशा को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। बारिश के कारण सड़कों की हालत और भी खराब हो गई है। इन रास्तों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिनसे पैदल राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अंबिकापुर-रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग अत्यंत जर्जर,फंस रहे वाहन और लग रहा जाम

अंबिकापुर से राजपुर और रामानुजगंज को जोड़ने वाला एनएच-343 अब सड़क कम,तालाब ज्यादा लग रहा है। इस पूरी सड़क पर हर कदम पर 10-10 फीट लंबे और 4 फीट गहरे गड्ढे ही नजर आते हैं। इन खतरनाक गड्ढों की वजह से पहले ही कई बसों का संचालन बंद हो चुका है। कुछ दिवस पूर्व इन्हीं गड्ढों ने मुसीबत खड़ी कर दी थी असोला गांव के पास एक बड़े गड्ढे में बस का पहिया फंस गया, जिससे वहां वाहनों की कतारें लग गईं और यातायात बाधित हो गया था कुछ इसी तरह की स्थिति आये दिन निर्मित होती रहती है। अंबिकापुर-रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग में बलरामपुर एवं राजपुर के बीच ग्राम पस्ता के पास बड़े-बड़े गड्ढों में बोल्डर एवं मुरम डाला गया था। अगस्त के महीने में छह ट्रकों के टायर फट गए थे ट्रक फंसने से घंटों जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी, मिली जानकारी अनुसार रामानुजगंज से अंबिकापुर के बीच तीन खंडों में टू लेन सड़क का निर्माण किया जाना है। इसके पूर्व सड़क को आवागमन लायक बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे जिससे सड़क के मरम्मत का कार्य चल रहा है परंतु मरम्मत के कार्य में घोर लापरवाही ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, जो परेशानी का सबब बन रहा है। बीते कई दिनों से बलरामपुर से राजपुर के बीच आवागमन प्रभावित हो रहा है। सड़क की मरम्मत के नाम पर ठेकेदार के द्वारा लीपापोती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

क्या कहते हैं लोग

अम्बिकापुर,बलरामपुर और अम्बिकापुर से सूरजपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा अम्बिकापुर निगम की सड़कें काफी खस्ताहाल हो चुकी हैं। लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं सड़क का मरम्मत जल्द होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को इस ओर मिल कर ध्यान देना चाहिए, सड़क की स्थिति को लेकर मैं स्वयं लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी से मुलाकात कर मांग करूंगा और वस्तुस्थिति से अवगत कराउंगा।

कृष्णा सिंह बाबा,श्रम जीवी पत्रकार कल्याण संघ

अम्बिकापुर और राजपुर की सड़क की हालत से पता चलता है कि सरकार को जनता के प्रति कोई सरोकार नही रह गया है,जल्द ही खराब सड़क को लेकर गोंडवाना गड़तंत्र पार्टी आंदोलन करेगी।

नीलेश पाण्डेय,प्रदेश महामंत्री गोंगपा

भाजपा सरकार में सड़कों को ध्यान देने वाला कोई नही है यह साफ साफ दिखाई दे रहा है, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है , जनता के समस्याओं को देखते हुए जल्द मरम्मत कार्य होना चाहिए

विमलेश तिवारी,सूरजपुर प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस

सरकार को जनता के समस्याओं की तनिक भी चिंता नही, संभाग में पांच मंत्री है जिनमे सी एम साहब सरगुजा संभाग से है लेकिन फिर भी राजपुर बलरामपुर एम जी रोड की हालत खराब है, सरकार को जनता की समस्याओं को देखते हुए जल्द मरम्मत कराना चाहिए

गुलाब कमरो,पूर्व विधायक

कल ही अम्बिकापुर से राजपुर काम से गया था सड़को की स्थिति देख कर वाहन चलाने में डर लगने लगा सरकार को संज्ञान लेकर जल्द मरम्मत कार्य करना चाहिए

पुष्पेंद्र राजवाड़े,अध्यक्ष कोरिया जनसहयोग समिति

जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा विरोध

सड़क की दुर्दशा पर विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष भी विरोध जता रहे है अलग अलग दलों के लोग अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं लेकिन इसका हल नही निकल रहा है। सूत्रों की माने तो इस सड़क का विधायक एवं सांसद ने निरक्षण कर सुधार के निर्देश भी दिए है बावजूद इसके स्थिति में सुधार न होने से लोगो मे नाराजगी है।

वाहन चालक परेशान,सुधार की मांग

अम्बिकापुर मनेन्द्रगढ़ मार्ग एवं अंबिकापुर राजपुर बलरामपुर से रहवासियों सहित वाहन चालकों ने सड़क के मरम्मत की मांग करते हुए कहा कि सड़क की मरम्मत होनी चाहिए, गाड़ियों का दम निकल जाए रहा है आय दिन दुर्घटनाएं हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं सरकार को इस पर जल्द संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

बिना ऑक्सीजन के रेफर की गई बच्ची की मौत,दो स्वास्थ्यकर्मी निलंबित

-संवाददाता-

अंबिकापुर,12 सितम्बर 2025 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिला अस्पताल में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है,जहां तीन माह की बच्ची को बिना ऑक्सीजन लगाए एम्बुलेंस से अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। रास्ते में बच्ची की मौत हो गई। मामले में ड्यूटी पर तैनात दो कर्मचारियों को जेडी (हेल्थ) डॉ. अनिल शुक्ला ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार, बलरामपुर के ग्राम पिंडरा निवासी सनम अगरिया की बेटी संजना अगरिया को मंगलवार को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसे निमोनिया के लक्षण थे, जिस पर शिशु रोग विशेषज्ञ ने तत्काल ऑक्सीजन लगाने और अंबिकापुर रेफर करने के निर्देश दिए। बावजूद इसके,अस्पताल प्रबंधन ने बच्ची को उसी एम्बुलेंस से भेजा जो पहले से ही एक अन्य मरीज को ले जा रही थी, और संजना की ऑक्सीजन हटा दी गई। रास्ते में बच्ची की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई थी। देर रात परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया और लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले की जांच बलरामपुर सीएमएचओ डॉ. बसंत सिंह ने की और जांच रिपोर्ट जेडी (हेल्थ) सरगुजा को सौंपी। जांच में दोषी पाए जाने पर स्टाफ नर्स नीता केशरी और स्वास्थ्यकर्मी सतीश अरकसेल को निलंबित कर दिया गया है। डॉ. अनिल शुक्ला ने अस्पताल के सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सूरजपुर में खुले में फेंका जा रहा मेडिकल वेस्ट,स्वास्थ्य पर मंडरा रहा गंभीर खतरा

-शमरोज खान-

सूरजपुर,12 सितम्बर 2025 (घटती-घटना)।

जिले में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा को ताक पर रखकर मेडिकल वेस्ट के खुले में निपटान का मामला सामने आया है, रिंग रोड किनारे बड़ी मात्रा में खतरनाक जैव चिकित्सा कचरा मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है,यहां इस्तेमाल की गई दवाइयां, इंजेक्शन, खून से सने ग्लव्स, कॉटन, पट्टियां,प्रेगनेंसी और मलेरिया टेस्ट किट, यहां तक कि एचआईवी जांच किट भी खुले में पड़ी मिली हैं, यह स्थिति न केवल आम नागरिकों बल्कि पर्यावरण और पशुओं के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है।

राहगीर बदबू और गंदगी से परेशान होकर नाक बंद करके गुजरने को मजबूर हैं,वहीं,आसपास घूम रहे मवेशी इस खतरनाक कचरे को खाते हुए देखे गए हैं,जिससे उनके बीमार होने का खतरा भी बढ़ गया है,यह स्थिति साफ दर्शाती है कि जिले में मेडिकल वेस्ट के निपटान को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। नियमों के अनुसार,

मेडिकल वेस्ट को सुरक्षित रूप से संग्रहित कर सरगुजा जिले स्थित अधिकृत बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सेंटर में भेजा जाना चाहिए,ताकि इसका वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से निपटान किया जा सके,लेकिन जिले के कई अस्पताल और निजी क्लीनिक इस व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, जानकारी के अनुसार, कई संस्थानों ने वर्षों से डिस्पोजल सेंटर को मेडिकल वेस्ट भेजना बंद कर दिया है, जिससे यह कचरा अब खुले में फेंका जा रहा है,स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर प्रशासन से शिकायत की है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है, उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही से महामारी फैल सकती है, लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर इतनी मात्रा में मेडिकल वेस्ट खुले में कैसे आ गया और संबंधित अधिकारियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, इस पूरे मामले पर सीएमएचओ डॉ. कपिल देव पैकरा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से मिली है, उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और इसकी तत्काल जांच करवाई जाएगी, साथ ही जो भी व्यक्ति या संस्था इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी डॉ. पैकरा ने यह भी स्वीकार किया कि खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने से संक्रमण फैलने की आशंका अत्यंत बढ़ जाती है और यह जनस्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, सूरजपुर में सामने आया यह मामला यह दिखाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था में कहीं न कहीं बड़ी खामी है। यह जरूरी हो गया है कि जिला प्रशासन इस दिशा में तत्काल कदम उठाए, दोषियों को चिन्हित करे और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए कठोर व्यवस्था लागू करे, साथ ही आम लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वे ऐसे मामलों की जानकारी समय रहते प्रशासन तक पहुंचा सकें।

CMYK

क्या दर्जन अनुरोध पत्रों के बावजूद भी नया पुलिस अधीक्षक कार्यालय महाविद्यालय परिसर में ही बनेगा?

पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान कोरबा सांसद तक मुख्यमंत्री से महाविद्यालय परिसर में कार्यालय ना बनाने की मांग कर रहे,क्या इनकी मांग मुख्यमंत्री मानेंगे?

महाविद्यालय परिसर में एसपी कार्यालय ना बने जिसके लिए लगातार पत्र मुख्यमंत्री को भेजे जा रहे हैं,क्या इसके बाद भी एसपी कार्यालय वहीं बनेगा?

मुख्यमंत्री को दो दर्जन से अधिक पत्र भेजा जा चुका है,महाविद्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय ना बने यही है मांग...

विरोध के बाद भी आखिर क्यों जिद पर अड़े हैं जिला प्रशासन के जिम्मेदार साथ सत्ताधारी दल के विधायक?

क्या परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय ना बने इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व विधायक व वर्तमान सांसद धरने पर बैठेंगे?

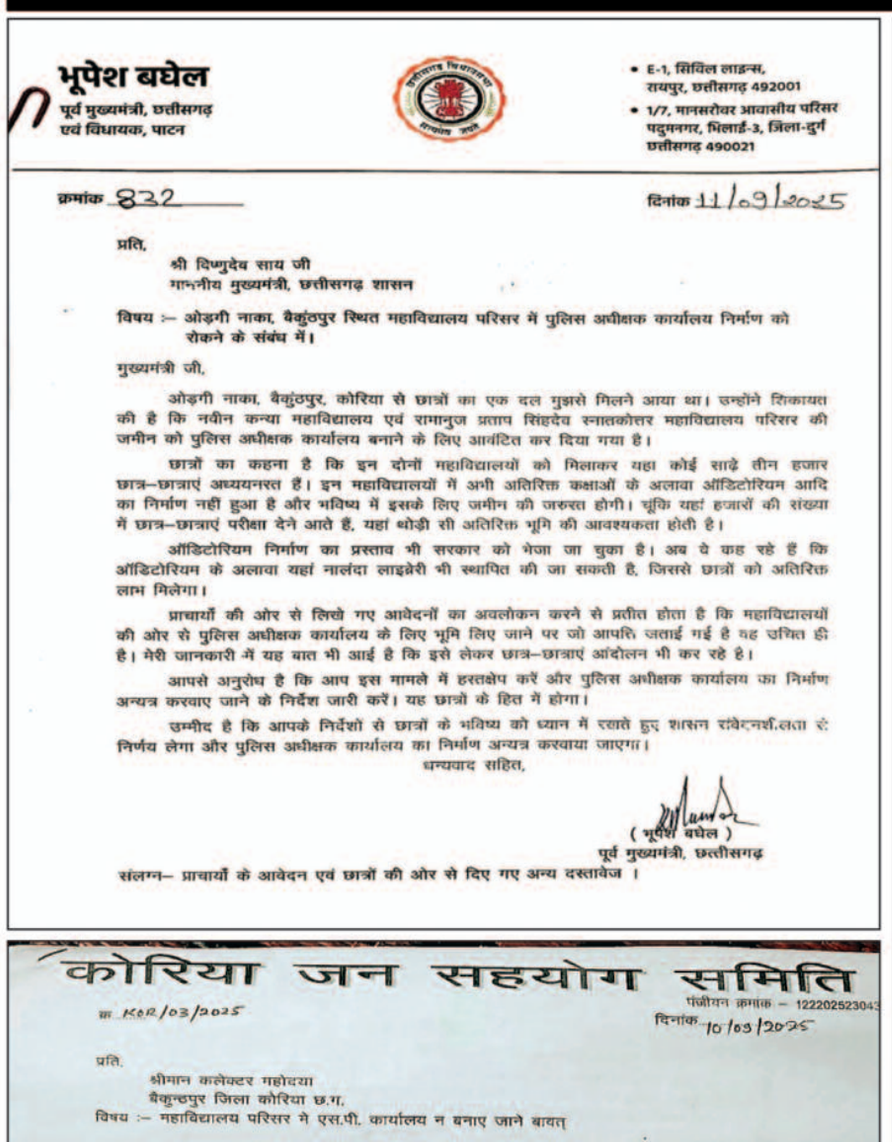

भूपेश बघेल
पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
एवं विधायक, पाटन

• E-1, सिविल लाइन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001
• 1/7, मानसरोवर आवासीय परिसर पदुमनगर, भिलाई-3, जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ 490021

क्रमांक 832 दिनांक 11/09/2025

प्रति,
श्री विष्णुदेव साय जी
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

विषय :- ओड़गी नाका, बैकुंठपुर स्थित महाविद्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय निर्माण को रोकने के संबंध में।

मुख्यमंत्री जी,

ओड़गी नाका, बैकुंठपुर, कोरिया से छात्रों का एक दल मुझसे मिलने आया था। उन्होंने शिकायत की है कि नवीन कन्या महाविद्यालय एवं रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर की जमीन को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बनाने के लिए आवंटित कर दिया गया है।

छात्रों का कहना है कि इन दोनों महाविद्यालयों को मिलाकर यहां कोई साढ़े तीन हजार छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन महाविद्यालयों में अभी अतिरिक्त कक्षाओं के अलावा ऑडिटोरियम आदि का निर्माण नहीं हुआ है और भविष्य में इसके लिए जमीन की जरुरत होगी। चूंकि यहां हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं परीक्षा देने आते हैं, यहां थोड़ी सी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है।

ऑडिटोरियम निर्माण का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा जा चुका है। अब वे कह रहे हैं कि ऑडिटोरियम के अलावा यहां नालंदा लाइब्रेरी भी स्थापित की जा सकती है, जिससे छात्रों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

प्राचार्यों की ओर से लिखे गए आवेदनों का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि महाविद्यालयों की ओर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए भूमि लिए जाने पर जो आपत्ति जताई गई है वह उचित ही है। मेरी जानकारी में यह बात भी आई है कि इसे लेकर छात्र-छात्राएं आंदोलन भी कर रहे हैं।

आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निर्माण अन्यत्र करवाए जाने के निर्देश जारी करें। यह छात्रों के हित में होगा।

उम्मीद है कि आपके निर्देशों से छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शासन संवेदनशीलता से निर्णय लेगा और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निर्माण अन्यत्र करवाया जाएगा।

धन्यवाद सहित,

(भूपेश बघेल)
पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

संलग्न- प्राचार्यों के आवेदन एवं छात्रों की ओर से दिए गए अन्य दस्तावेज।

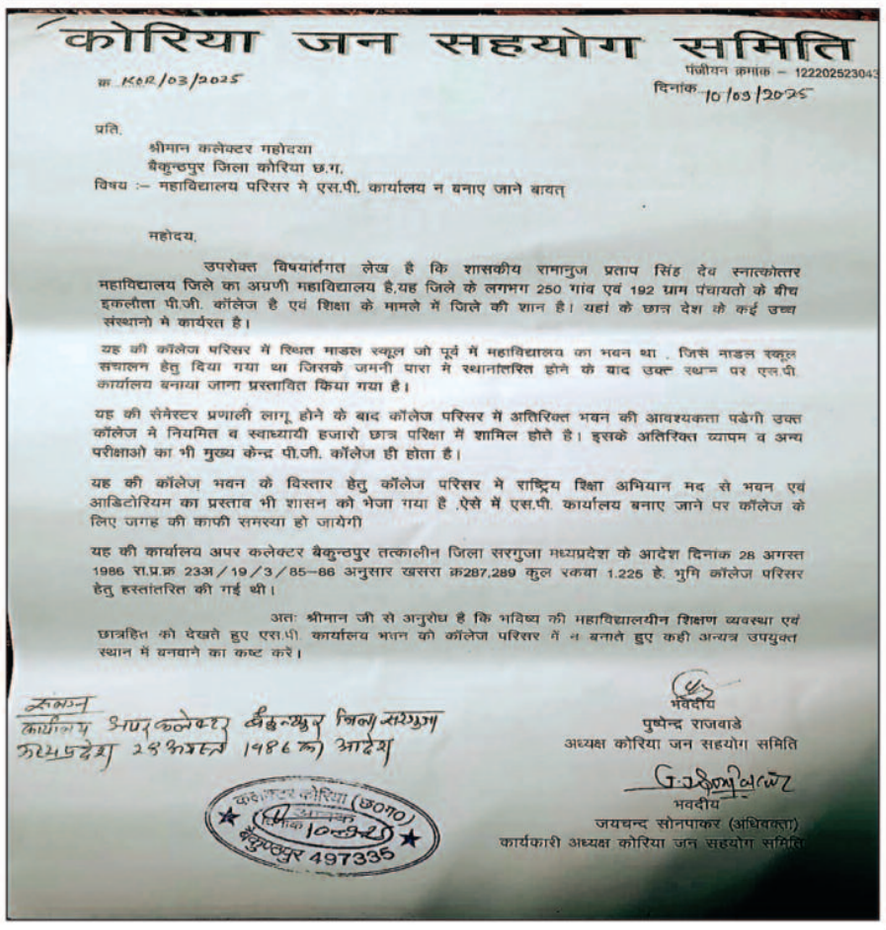

कोरिया जन सहयोग समिति

पंजीयन क्रमांक - 122202523043

क्र. KOR/03/2025 दिनांक 10/09/2025

प्रति,
श्रीमान कलेक्टर महोदया
बैकुन्ठपुर जिला कोरिया छ.ग.

विषय :- महाविद्यालय परिसर मे एस.पी. कार्यालय न बनाए जाने बावत्

महोदय,

उपरोक्त विषयांर्तगत लेख है कि शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिले का अग्रणी महाविद्यालय है,यह जिले के लगभग 250 गांव एवं 192 ग्राम पंचायतो के बीच इकलौता पी.जी. कॉलेज है एवं शिक्षा के मामले में जिले की शान है। यहां के छात्र देश के कई उच्च संस्थानो मे कार्यरत है।

यह की कॉलेज परिसर में स्थित माडल स्कूल जो पूर्व में महाविद्यालय का भवन था, जिसे माडल स्कूल संचालन हेतु दिया गया था जिसके जमनी पारा में स्थानांतरित होने के बाद उक्त स्थान पर एस.पी. कार्यालय बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

यह की सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के बाद कॉलेज परिसर में अतिरिक्त भवन की आवश्यकता पडेगी उक्त कॉलेज मे नियमित व स्वाध्यायी हजारो छात्र परिक्षा में शामिल होते है। इसके अतिरिक्त व्यापम व अन्य परीक्षाओ का भी मुख्य केन्द्र पी.जी. कॉलेज ही होता है।

यह की कॉलेज भवन के विस्तार हेतु कॉलेज परिसर मे राष्ट्रिय शिक्षा अभियान मद से भवन एवं आडिटोरियम का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है .ऐसे में एस.पी. कार्यालय बनाए जाने पर कॉलेज के लिए जगह की काफी समस्या हो जायेगी

यह की कार्यालय अपर कलेक्टर बैकुन्ठपुर तत्कालीन जिला सरगुजा मध्यप्रदेश के आदेश दिनांक 28 अगस्त 1986 रा.प्र.क्र 233अ/19/3/85-86 अनुसार खसरा क्र287,289 कुल रकबा 1.225 हे. भुमि कॉलेज परिसर हेतु हस्तांतरित की गई थी।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि भविष्य की महाविद्यालयीन शिक्षण व्यवस्था एवं छात्रहित को देखते हुए एस.पी. कार्यालय भवन को कॉलेज परिसर में न बनाते हुए कही अन्यत्र उपयुक्त स्थान में बनवाने का कष्ट करें।

भवदीय
पुष्पेन्द्र राजवाडे
अध्यक्ष कोरिया जन सहयोग समिति

भवदीय
जयचन्द सोनपाकर (अधिवक्ता)
कार्यकारी अध्यक्ष कोरिया जन सहयोग समिति

-रवि सिंह-

कोरिया,12 सितंबर 2025 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के जिला मुख्यालय में स्थित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन के निर्माण की शुरुआत और इसके लिए हुए भूमिपूजन के बाद लगातार यह मांग उठ रही है कि यह निर्णय सही नहीं है और महाविद्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निर्माण महाविद्यालय के विस्तार को प्रभावित करेगा साथ ही यह महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की स्वतंत्रता को भी बाधित करेगा,विरोध छात्र भी कर रहे हैं महाविद्यालय के पूर्व छात्र भी कर रहे हैं,मुख्यालय सहित जिले के लोग भी कर रहे हैं और प्रमुख विपक्षी दल भी इस मामले में अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहा है और इस निर्माण की के लिए चयनित और आबंटित भूमि को गलत ठहरा रहा है। इस बीच क्षेत्रीय सांसद जो कांग्रेस पार्टी से हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी अब मामले में अपने पत्र लिखकर किए गए विरोध के माध्यम से कूद पड़े हैं और उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस निर्माण के लिए अन्यत्र स्थान तलाशने की गुजारिश की है,इसे गलत भूमि आबंटन बताया।

बताया जा रहा है कि अभी दो दर्जन से अधिक पत्र मुख्यमंत्री तक भेजे जाने का क्रम जारी है और अब तक भेजे लिखे गए पत्रों के विषय में ही कोई सुनवाई कोई ऐसा निर्णय सामने सरकार या मुख्यमंत्री का नहीं आया है जिससे यह समझा जा सके या जिससे यह प्रतीत हो सके कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए अन्यत्र भूमि की तलाश होगी और महाविद्यालय परिसर में नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय निर्माण पर रोक लगेगी। वैसे क्या विरोध और कई दर्जन अनुरोध पत्रों के बावजूद भी नया पुलिस अधीक्षक कार्यालय महाविद्यालय परिसर में ही बनेगा और अब इस निर्णय में बदलाव की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है यह एक बड़ा सवाल है। जिला प्रशासन,साथ ही सत्ताधारी दल के विधायक का रुख नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निर्माण के प्रति सकारात्मक ही सामने आ रहा है वहीं विधायक के अडिग और निर्णय में बदलाव की बात खारिज करने के बाद से ही जिलाध्यक्ष भाजपा का भी बयान सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने भी निर्णय को लेकर यही कहा कि निर्माण और विकास को अवरुद्ध किए जाने की जगह उसमे सहभागी बनने का प्रयास किया जाना चाहिए और जहां तक महाविद्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय निर्माण और तत्पश्चात महाविद्यालय के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध न होने की बात की जा रही है इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की भूमि जिस पर वर्तमान में कार्यालय है उसे प्रदान किया जाएगा ऐसा उन्होंने कहा। उनके अनुसार भविष्य में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मानस भवन या उसके आसपास नए भवन में स्थापित किया जायेगा कुल मिलाकर प्रशासन और सत्ताधारी दल के नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निर्णय में बदलाव संभव नहीं है। वैसे नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निर्माण के समय ही सही इस संबंध में सहमति और इस निर्णय के समर्थन में ही सही विधायक और जिलाध्यक्ष साथ साथ नजर आ रहे हैं या कहें एक आम राय या विचार प्रकट कर एकजुटता दिखा रहे हैं।

क्षेत्रीय सांसद ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, महाविद्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय निर्माण के निर्णय को बदलने की मांग की

मामले में क्षेत्रीय सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय निर्माण के लिए महाविद्यालय परिसर की भूमि की जगह अन्य किसी स्थल का चयन कर निर्माण की मांग की है, क्षेत्रीय सांसद ज्योत्सना महंत ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में लिखा है कि यह निर्णय महाविद्यालय सहित छात्र हित में सही नहीं है,इस निर्णय से महाविद्यालय का विस्तार प्रभावित होगा। उन्होंने महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की संख्या का उल्लेख करते हुए भविष्य में भवन आवश्यकताओं की बात कहते हुए यह मांग की है कि यह निर्णय महाविद्यालय के विस्तार को प्रभावित करेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यह भवन अन्य स्थान पर भी बनाया जा सकता है और इस निर्णय को लेकर पुनः विचार की आवश्यकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने भी मुख्यमंत्री को लिखा पत्र,निर्णय बदलने की मांग

मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखते हुए यह मांग की है कि महाविद्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निर्माण सही निर्णय नहीं प्रतीत हो रहा है, महाविद्यालय में वर्तमान में 3200 छात्रों के अध्ययनरत होने की बात कहते हुए उन्होंने यह उल्लेखित किया है कि महाविद्यालय परिसर में छात्रों के लिए अभी अतिरिक्त कक्षों की भी आवश्यकता है वहीं वहां ऑडिटोरियम के निर्माण भी आवश्यकता है जिसका प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। उन्होंने नालंदा परिसर जो जिले के लिए स्वीकृत है उसका निर्माण महाविद्यालय परिसर में किया जाए जो अच्छा निर्णय होगा यह भी पत्र में लिखते हुए यह अनुरोध किया है कि पूर्व में लिए निर्णय जिसमे महाविद्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है उसे बदलने की आवश्यकता है और भविष्य में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए अन्य जगह स्थल चयन कर पुलिस अधिक्षक कार्यालय बनाया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मामले में पत्र में यह भी उल्लेखित किया है कि यह पत्र कोरिया जिले से पहुंचे कुछ लोगों के अनुरोध पर उन्होंने लिखा है जो महाविद्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जगह महाविद्यालय का ही या शिक्षा संबधी व्यवस्थाओं का ही विस्तार चाहते हैं और छात्र इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं उन्होंने पत्र लिखा है।

दर्जनों पत्र मुख्यमंत्री को भेजे जाने की है तैयारी,पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की होगी मांग

बताया जा रहा है कि स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन के अड़ियल रवैए से निराश होकर साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष के द्वारा दिए गए बयान के बाद जिसमें उन्होंने निर्माण और विकास में अवरोधक बनाने से परहेज करने की बात की है अब मुख्यमंत्री से ही महाविद्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का विरोध कर रहे लोगों को उम्मीद रह गई है,अब कई दर्जन पत्र मुख्यमंत्री को भेजे जाने की तैयारी हो रही है जो भेजा भी जा रहा है, मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप के लिए यह पत्र भेजे जाएंगे और उनसे यह मांग की जाएगी कि इस निर्णय पर पुनः विचार किया जाए। पत्र भेजकर महाविद्यालय की भविष्य की आवश्यकताओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराना और उनसे महाविद्यालय परिसर की भूमि को पुनः महाविद्यालय को आवंटित करवाने की मांग प्रमुख होगी। मुख्यमंत्री ही मामले में अब रास्ता निकाल सकते हैं और वह महाविद्यालय की भूमि को पुनः महाविद्यालय को वापस लौटा सकते हैं यह लोगों का मानना है।

पुलिस सुरक्षा में तेजी से हो रहा निर्माण कार्य

पुलिस अधीक्षक कार्यालय निर्माण पुलिस सुरक्षा में तेजी से किया जा रहा है,पुलिस निर्माण के दौरान किसी तरह की रुकावट आने से पहले ही निर्माण करने की कोशिश में लगी है और वह निर्माण जल्द पूरा हो जाए इसलिए सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात कर रखी है,वैसे पुलिस विभाग के किसी निर्माण मामले में कोई सीधे तौर पर निर्माण को नुकसान पहुंचाने या अन्य कोई हिमाकत सोचेगा भी नहीं लेकिन पुलिस अपनी तरफ से सजग और सतर्क होकर इस निर्माण को जल्द पूरा करने के प्रयास में लगी है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय निर्माण के दौरान पर्यावरण को भी पहुंचाया जा रहा नुकसान,पेड़ों को काटने की बजाए उखाड़कर आंधी तूफान से गिरा होना बताए जाने का प्रयासःसूत्र

सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक कार्यालय निर्माण के दौरान पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है,महाविद्यालय परिसर की जिस भूमि पर नया भवन बनाया जा रहा है उसमें लगे हरे भरे पेड़ अब बीते दिनों की बात होने जा रहे हैं। पेड़ों को हटाने और पर्यावरण विरोधी न होने दोनों विषय में फिट बैठने के लिए पेड़ों को काटने की बजाए उखाड़ा जा रहा है जिससे किसी समय भी यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जाने की बात सामने आए यह कहा जाए कि आंधी तूफान से पेड़ उखड़ कर खुद गिर गए थे। वैसे पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत पेड़ लगाने वाले जिला प्रशासन द्वारा ही यदि पेड़ों की कटाई की या उन्हें उखाड़ने की अनुमति दी जा रही है तो यह चिंताजनक विषय है। पेड़ों को हटाने यह नई तरकीब पहली बार अपनाई जा रही है ऐसा माना जा रहा है। बताया जा रहा है पेड़ों की संख्या कम भी नहीं है यह संख्या बड़ी है और ऐसा किया जाना निश्चित रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जाने का मामला है,वैसे प्रशासन जहां खुद की बात आती है ऐसे मामलों में मौन हो जाता है या कोई तरकीब निकाल लेता है और वैसा ही हो भी रहा है पेड़ों को काटने की जगह उखाड़ा जा रहा है।

कोरिया जन सहयोग समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन सौप नवीन एसपी कार्यालय को कालेज परिसर से अन्यत्र किसी उपयुक्त स्थान पर बनाने की मांग

कोरिया जन सहयोग समिति पंजीकृत गैर राजनीतिक सोसायटी ने कलेक्टर कार्यालय कोरिया को ज्ञापन भेज कर नवीन एसपी कार्यालय को कालेज परिसर से अन्यत्र किसी उपयुक्त स्थान पर बनाने मांग पत्र भेजा है समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े एवं कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता जयचन्द सोनपाकर ने बताया कि शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नात्कोत्तर महाविद्यालय जिले का अग्रणी महाविद्यालय है,यह जिले के लगभग 250 गांव एवं 192 ग्राम पंचायतो के बीच इकलौता पी.जी. कॉलेज है एवं शिक्षा के मामले में जिले की शान है। यहां के छात्र देश के कई उच्च संस्थानो में कार्यरत है और कॉलेज का मान भी बढाया है पुष्पेंद्र राजवाड़े एवं अधिवक्ता जयचन्द सोंपाकर ने बताया कि कॉलेज परिसर में स्थित माडल स्कूल जो पूर्व में महाविद्यालय का भवन था जिसे माडल स्कूल संचालन हेतु दिया गया था जिसके जमनी पारा में स्थानांतरित होने के बाद उक्त स्थान पर एस.पी. कार्यालय बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। कॉलेज सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के बाद कॉलेज परिसर में अतिरिक्त भवन की आवश्यकता पडेगी उक्त कॉलेज में नियमित व स्वाध्यायी हजारो छात्र परीक्षा में शामिल होते है। इसके अतिरिक्त व्यापम व अन्य परीक्षाओं का भी मुख्य केन्द्र पी.जी. कॉलेज ही होता है। अधिवक्ता जयचन्द ने बताया कि जानकारी मिली है कि कॉलेज भवन के विस्तार हेतु कॉलेज परिसर मे राष्ट्रीय शिक्षा अभियान मद से भवन एवं ऑडिटोरियम का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है,ऐसे में एसपी कार्यालय बनाए जाने पर कॉलेज के लिए जगह की काफी समस्या हो जायेगी अधिवक्ता ने बताया कि कार्यालय अपर कलेक्टर बैकुंठपुर तत्कालीन जिला सरगुजा मध्य प्रदेश के आदेश दिनांक 28 अगस्त 1986 रा.प्र.क्र. 233/19/3/85-86 अनुसार खसरा क्र 287,289 कुल रकबा 1.225 हे. भुमि कॉलेज परिसर हेतु हस्तांतरित की गई थी लेकिन किसी कारण इसका राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज नही हो सका कोरिया जनसहयोग समिति की ओर से पुष्पेंद्र राजवाड़े एवं जयचन्द सोंपाकर ने भविष्य की महाविद्यालयीन शिक्षण व्यवस्था एवं छात्रहित को देखते हुए एस.पी. कार्यालय भवन को कॉलेज परिसर में न बनाते हुए कहीं अन्यत्र उपयुक्त स्थान में बनवाने की मांग किया है।

नौसिखिए तहसीलदार का बचकाना फैसला?

क्या तहसीलदार साहब की डिमांड पूरी नहीं होगी...तो कुछ भी लिखकर प्रकरण कर देंगे खारिज?

भैयाथान के नये नवेले तहसीलदार ने राजस्व अमले की गलती पर प्रार्थी का आवेदन किया खारिज?

भैयाथान तहसीलदार का अनोखा फैसला देखकर ऐसा लगा कि न्याय की कुर्सी में नहीं किसी फिल्म के न्यायालय में बैठकर दिया फैसला?

3 साल तहसील न्यायालय में कब्जा हटाने का प्रकरण लंबा खींचकर और अंत में यह लिखकर खारिज किया गया कि अनावेदक का हस्ताक्षर नहीं।

आवेदक/अनावेदक का हस्ताक्षर लेने की जिम्मेदारी किसकी थी,प्रार्थी की या फिर राजस्व अमले की?

जिस बात का संज्ञान पहली पेशी में हो जाना था,उसके लिए लगा 3 साल का समय,परिणाम भी ढाक के तीन पात की कहावत को चरितार्थ करता है...

-ओकार पाण्डेय-

सूरजपुर,12 सितंबर 2025 (घटती-घटना)। सत्यमेव जयते यह स्लोगन हमें हर न्यायालय में देखने को मिल सकता है,और कहा भी जाता है कि अंतिम विजय सत्य की ही होती है। सत्य हर न्यायालय में जीत सकता है, पर एक ही न्यायालय है जहां सत्य हार जाता है, वह न्यायालय है राजस्व न्यायालय। जहां पर सत्य का कोई मोल नहीं,सिर्फ पैसे का बोलबाला,पैसा दीजिए और फैसला अपने पक्ष में लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है,तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी ताजा मामला सूरजपुर जिले के भैयाथान तहसील कार्यालय का सामने आया है। ओड़गी तहसील के ग्राम इंदरपुर भू स्वामी यानी कि प्रार्थी ने अपने जमीन पर कब्जे का प्रकरण न्यायपूर्वक करने के लिए ओड़गी तहसील कार्यालय से भैयाथान तहसील कार्यालय प्रकरण को स्थानांतरण करवाया,ताकि निष्पक्ष तरीके से प्रकरण का निपटारा हो सके। पर उसे यह नहीं पता था कि राजस्व के न्यायालय में बैठे भ्रष्ट अधिकारी ऐसा होने नहीं देंगे। भैयाथान राजस्व न्यायालय में चल रहा प्रकरण 3 साल बाद इस नतीजे के साथ खारिज किया गया, वहां के तहसीलदार द्वारा जो फैसला हुआ देखकर लोग उस फैसले पर हंस रहे हैं, और मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तहसीलदार ने बचकाना फैसला दे दिया हो।

पंचनामा कॉपी

न्यायालय तहसीलदार भैयाथान जिला सूरजपुर (छ.ग.)

.......................आवेदक

प्रति

निवासी ग्राम इंदरपुर तहसील ओड़गी जिला सूरजपुर (छ.ग.)

.......................अनावेदक

(आदेश दिनांक 10.09.2025)

प्रकरण का संक्षिप्त इस प्रकार है की आवेदिका श्रीमती मंजू सिंह पति विनोद सिंह निवासी ग्राम इंदरपुर तहसील ओड़गी जिला सूरजपुर छ.ग. द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया है की ग्राम इंदरपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 819/10 रकबा 0.40 हे. भूमि (जिसे आगे वादभूमि कहा गया है) आवेदिका के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि को आवेदिका द्वारा पंजी बद्ध विक्रय नामा दिनांक 06.10.2017 के माध्यम से क्रय किया है। आवेदिका द्वारा वादभूमि का सीमांकन दिनांक 10.04.2023 को कराया गया है। उक्त भूमि में से सड़क किनारे 5 मीटर पर अनावेदिका रमजुति पुत्री उदई ,निवासी ग्राम इंदरपुर द्वारा मकान निर्माण किया जा रहा है। अनावेदिका द्वारा वादभूमि पर किये जा रहे निर्माण कार्य को हटा कर आवेदिका को कब्जा दिए जाने हेतु मय आवेदन ,पंजी बद्ध विक्रय नामा दिनांक 06.10.2017 की प्रति , न्यायालय तहसीलदार ओड़गी के रा.प्र.क्र. 202303261100006 अ 12 / 2022-23 पक्षकार मंजू सिंह प्रति छ.ग. शासन की प्रति , व्यपवर्तन प्रमाण पत्र की प्रति, बी 1 वर्ष 2021-22 सहित पेश किया है।

क्रमशः 02

तहसीलदार
भैयाथान,जिला-सूरजपुर(छ.ग.)

निराकरण वि. घनश्याम तिवारी एवं अन्य, 2016 छ.ग.ग.ज. 27]

प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है की आवेदिका द्वारा दिनांक 10.04.2023 को खसरा नम्बर 819/10 रकबा 0.40 हे. भूमि का सीमांकन कराया गया है। प्रकरण में संलग्न उक्त सीमांकन पंचनामा की छायाप्रति में अनावेदिका या कब्जेदार के उपस्थिति का कोई उल्लेख नही है और न ही उक्त पंच नामा में अनावेदिका का हस्ताक्षर है। उक्त सीमांकन पंचनामा में उक्त भूमि पर किसका कब्जा है कोई उल्लेख नही है और न ही उक्त सीमांकन में फील्ड बुक संलग्न है।

अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है।
प्रकरण मूलतः न्यायालय तहसीलदार ओड़गी को प्रेषित हो

तहसीलदार
भैयाथान

तहसीलदार
भैयाथान,जिला-सूरजपुर(छ.ग.)

तहसीलदार साहब के द्वारा खारिज प्रकरण की कॉपी

स्थानीय लोगों और आवेदिका के दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न

सवालः क्यों तहसील और राजस्व विभाग में लगातार भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप लगता हैं?

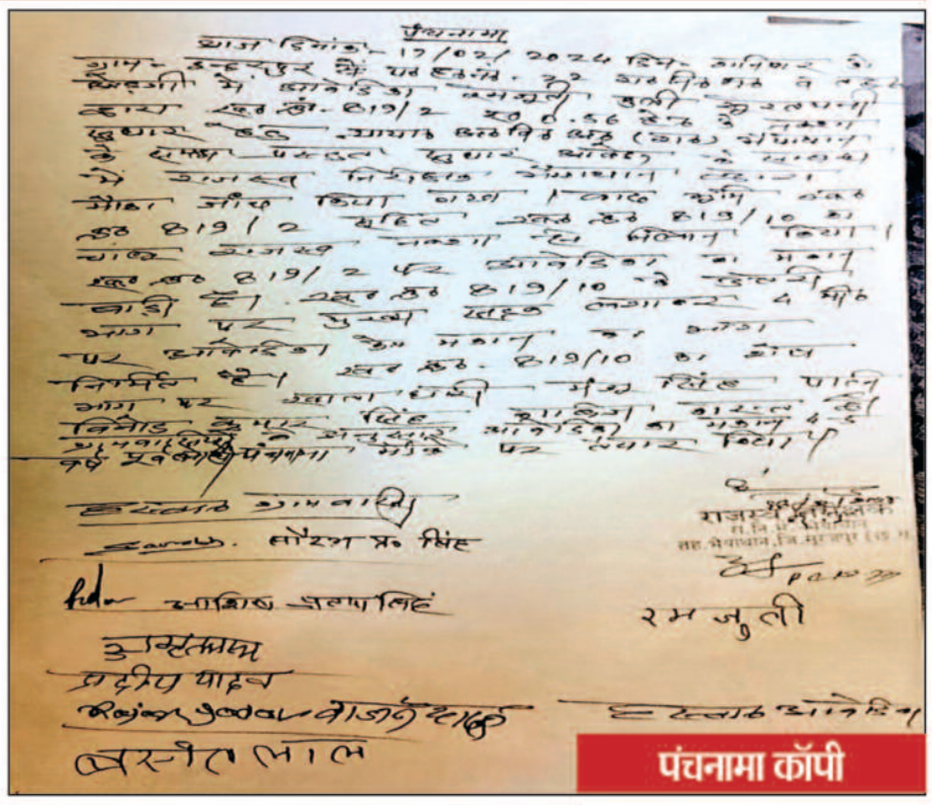

सवालः क्या न्याय दिलाने के बजाय रिश्वत और दबाव का खेल चलता है?

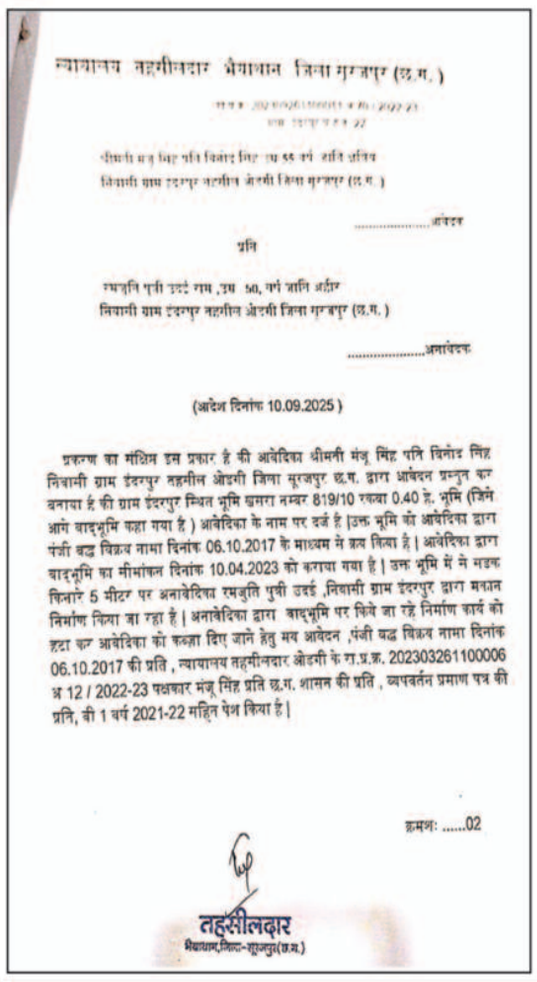

सवालः क्या अब जनता को सीधे न्यायालय (कोर्ट) का दरवाजा खटखटाना बंद कर देना चाहिए?

सवालः क्या सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जनता को तहसील स्तर पर ही न्याय मिले, ताकि हर साधारण नागरिक कोर्ट के चक्कर काटने से बचे?

सवालः जब जमीन की रजिस्ट्री और निपटान की प्रक्रिया अनेक सरकारी अधिकारियों पटवारी, आर.आई., तहसीलदार व अन्य कर्मियों के हस्तक्षेप से होकर गुजरती है, तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले पर्याप्त तंत्र मौजूद होने के बात भी बेतुका फैसला क्यों होता है?

सवालः क्या यह मानना जायज़ है कि एक ही प्रकरण कई स्तरों पर जाकर सत्यापन के बाद भी अचानक निर्णयों से प्रभावित कर दे और यदि हाँ, तो ऐसे निर्णयों के पीछे जिम्मेदारियों का लेखा-जोखा कौन तय करेगा?

सवालः यदि बिक्री के बाद विक्रेता ने फिर भी जमीन पर कब्ज़ा कर लिया है तो क्या तहसील कार्यालय के पास ऐसे मामलों में तत्काल प्रभाव से या प्रभावी वैधानिक उपाय उपलब्ध नहीं हैं जो देश के नागरिकों को उनके अधिकार तुरंत दिला सकें?

सवालः क्या यह कार्य है कि एक नागरिक को न्याय पाने के लिए बार-बार तहसील के चक्कर काटने पड़े,जबकि भूमि रजिस्ट्री का अंतिम निर्णय कई सरकारी चरणों से होकर गुजरता है?

सवालः क्या ऐसी परिस्थितियों में राज्य का दायित्व नहीं बनता कि वह तहसील स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध सुनवाई के सख्त मानक लागू करे ताकि आम जनता को कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत ही न पड़े?

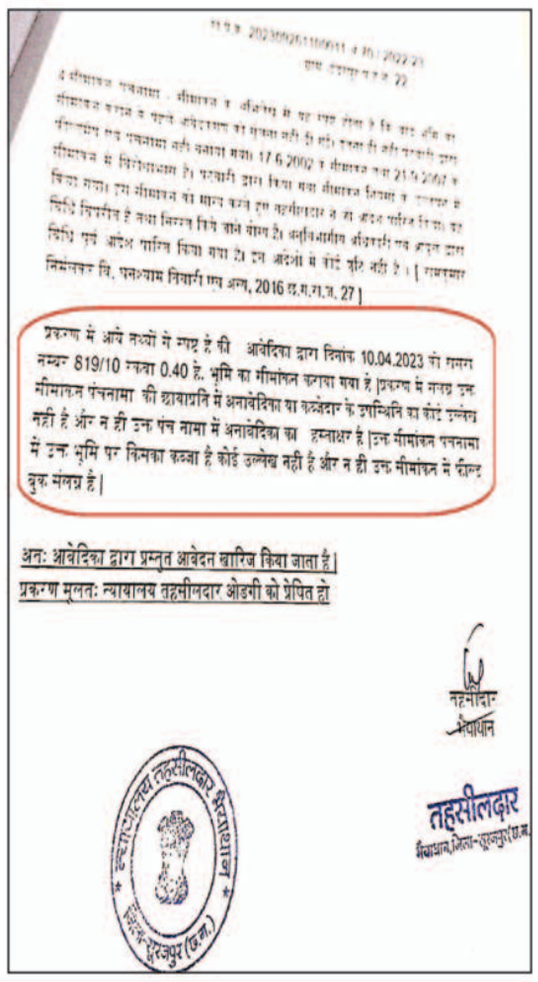

सवालः क्या सरकार को राजस्व-प्रक्रियाओं को और अधिक डिजिटल, ट्रैक-एबिल और ऑडिटी-फ्रेंडली बनाकर भ्रष्टाचार घटाना चाहिए या फिर यदि तहसील स्तर पर सुधार संभव न हो तो उसके विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए?

सवालः क्या यह मांग वाजिब नहीं होगी कि ऐसे मामलों में त्वरित निवारण और जनहित की दृष्टि से उच्च स्तरीय पारदर्शी जांच की जाए ताकि दोहराव व दुरुपयोग रोके जा सके?

सवालः क्या सरकार को यह विचार करना चाहिए कि तहसील कार्यालयों की मौजूदा व्यवस्थाएँ यदि व्यापक स्तर पर जवाबदेही व पारदर्शिता न दे रही हों, तो क्या उनकी कार्यप्रणाली में संरचनात्मक बदलाव या निगरानी तंत्र लागू किए जाएँ?

अन्यायपूर्ण व्यवस्था और फैसले पर आवेदिका का सनसनीखेज आरोप

ग्राम इन्दरपुर की भूमि स्वामी आवेदिका का आरोप है कि उनके जमीन प्रकरण (प्रकरण संख्या 20230926110001 1/ए-70-2022-23) के निपटारे में तहसील-स्तर पर गंभीर अनियमितताएं हुईं और उन्हें न्याय से वंचित किया गया। आवेदिका का कहना है कि जब उन्होंने मामले को भैयाथान में जाने दिया तो तहसील-कर्मियों ने उनसे कथित मांगें कीं और कई बार आदेश बंदी/टालमटोल के चलते उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। आवेदिका के मुताबिक,तत्कालीन तहसीलदार संजय राठौर ने कहा कि मामला अगर भैयाथान में रहेगा तो वह ÷आदेश कर देंगे पर बाद में महंगी उपहार और नकद की मांगें सामने आईं (आरोप में आई-फ़ोन जैसी मांग का उल्लेख किया गया है।) और आंशिक भुगतान लेने के बाद भी फाइल कई महीनों तक तहसीलदार के पास पड़ी रही। बाद में संजय राठौर को निलंबित कर दिया गया था।? जिन पर पहले भी भूमि नामांतरणों के संदिग्ध मामलों में कार्रवाई की खबरें आई थीं। यह निलंबन स्थानीय मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ था। आरोप के मुताबिक, संजय राठौर के निलंबन के बाद आए नए तहसीलदार शिव नारायण राठिया के कार्यकाल में भी आवेदिका ने वही पैटर्न अनुभव किया। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि तहसील के कुछ कर्मियों ने साफ कहा कि एक तय राशि का समझौता पहले से था और प्रकरण पर तत्काल निर्णय दिए जाने के लिए भुगतान की मांग की जा रही थी। आवेदिका ने बताया कि जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो उनके आवेदन की सुनवाई टाल दी गई और 10/09/2025 को उनका आवेदन खारिज कर दिया गया।

आवेदिका विभिन्न माध्यमों से प्रशासन से मांग कर रही हैं...

उनके प्रकरण की न्यायिक/प्रशासनिक रूप से निष्पक्ष और त्वरित पुनः जांच की जाए,जो भी कर्मियों ने अनुचित दबाव/राशि की मांग की,उन पर कड़ी विभागीय और आवश्यक कानूनी कार्रवाई हो, रेवेन्यू प्रथाओं की समीक्षा कर पारदर्शिता और ट्रैकिंग-मैकेनिज्म लागू किया जाए ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

समाचार का परीक्षित स्वर और चेतावनी

यह रिपोर्ट आवेदिका के दावों और स्थानीय स्रोतों पर आधारित है। हमारी रिपोर्ट का उद्देश्य किसी व्यक्ति को बिना प्रमाण बदनाम करना नहीं है पर सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि रेवेन्यू विभाग और शासन-स्तर पर यह स्पष्ट किया जाए कि क्या ऐसे आरोप सत्य हैं और किस तरह की सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। जब तक त्वरित और पारदर्शी जांच नहीं होती,तब तक जमीन मालिकों का भरोसा बहाल नहीं हो पाएगा।

भैयाथान के नये नवेले तहसीलदार ने राजस्व अमले की गलती पर प्रार्थी का आवेदन किया खारिज?

विकासखंड ओडगी के ग्राम पंचायत इंदरपुर निवासी ने अपने हक और रिकॉर्ड की भूमि पर बेजा कब्ज़ा हटाए जाने और विवाद से किनारा करने के लिए उक्त भूमि का तीन बार सीमांकन कराया। यह प्रक्रिया सन 2002, 2007 और 2024 में संपन्न हुई। तीन बार सीमांकन होने पर भी राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सीमा विवाद और बेजा कब्जा पर कोई निर्णयकारी कार्यवाही नहीं किया। त्रस्त होकर आवेदिका ने तहसीलदार के समक्ष बेजा कब्जा हटाए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया और न्याय की आशा में ओडगी तहसील कार्यालय से अपने प्रकरण को भैयाथान तहसील कार्यालय में स्थानांतरित कराया, ताकि निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके। परंतु 3 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी आवेदिका के हाथ कुछ नहीं आया और वर्तमान तहसीलदार भैयाथान ने यह कहकर मामले को खारिज कर दिया की कराए गए सीमांकन और जमा किए गए दस्तावेजों में त्रुटियां हैं,फील्ड बुक तैयार नहीं है, सीमांकन के समय अनावेदक अनुपस्थित था और सीमांकन पंचनामा में अनावेदक के हस्ताक्षर नहीं है। मामले में बड़ा सवाल यह है कि जब किसी भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है,तो राजस्व विभाग के कर्मचारी ,पटवारी,आर आई विधिवत सीमांकन कार्यवाही करते हैं। आवेदक के साथ-साथ अनावेदक एवं ऐसे व्यक्ति,संस्था की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जो तत्संबंधित भूमि से लगी भूमि के स्वामी अथवा कब्जाधारी होते हैं। मौके पर ही सीमांकन कर फील्ड बुक तैयार किया जाता है, और इसके साथ ही सीमांकन का पंचनामा तैयार किया जाता है। जिसमें समस्त हितबद्ध पक्षकार,आवेदक,अनावेदक सभी के हस्ताक्षर लेने अनिवार्य होते हैं। उनकी गैरमौजूदगी में सीमांकन का कार्य नहीं किया जा सकता। बाकायदा सीमांकन का शुल्क अदा किया जाता है। यदि सीमांकन में त्रुटि की जाए या सीमांकन संबंधी दस्तावेजों में त्रुटि हो, आधे अधूरे हों, तो सारा दोस्त राजस्व विभाग के कर्मचारियों का होता है। इसमें आवेदक की कोई त्रुटि नहीं होती, इस आधार पर आवेदक का प्रकरण खारिज किया जाना न्याय की हत्या के समान है।

तहसीलदार ने सीमांकन दस्तावेजों में त्रुटि बता प्रकरण खारिज किया, सीमांकनकर्ता कर्मचारी, अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब करना था या पूरा प्रकरण ख़ारिज करना था?

जिस प्रकरण को भैयाथान तहसीलदार ने सीमांकन दस्तावेजों में त्रुटि बताकर खारिज किया है,उसमें उन्हें सीमांकनकर्ता कर्मचारी, अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब। तलब करना चाहिए था। प्रकरण को खारिज करने का जो कारण तहसीलदार ने अपने फैसले में लिखा है, उसके अनुसार पूर्व में किए गए 2002 और 2007 में सीमांकन में विरोधाभास है। पर यह विरोधाभास आवेदिका के कारण नहीं है, बल्कि दोनों बार सीमांकन करने गए अधिकारी कर्मचारियों के कारण है। इसके साथ ही प्रकरण को खारिज करते समय भैयाथान तहसीलदार ने आदेश में लिखा है कि वर्तमान में किए गए सीमांकन में अनावेदक का हस्ताक्षर नहीं है,अनावेदक की उपस्थिति सीमांकन के समय परिलक्षित नहीं होती एवं फील्ड बुक तैयार नहीं है। क्या तहसीलदार को इतना भी नहीं पता की फील्ड बुक तैयार करने वाला, सीमांकन के समय पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना एवं पंचनामा प्रतिवेदन पर पक्षकारों का हस्ताक्षर लेना पटवारी और आर आई का कार्य है। इसमें किसी पक्षकार और आवेदक का कोई भूमिका नहीं होता। इस आधार पर प्रकरण कैसे खारिज किया जा सकता है?? इन्हीं आधार पर आवेदिका के ही प्रकरण को खारिज कर दिया गया जो कि बडा ही हास्यास्पद है। यहां या तो न्यायकर्ता अनुभवहीन और नौसीखिया नजर आता है, या फिर आशानुकूल चढ़ावे के अभाव में यह फैसला लिया गया है।

जिस बात का संज्ञान पहली पेशी में हो जाना था,उसके लिए लगा 3 साल का समय, परिणाम भी ढाक के तीन पात

राजस्व न्यायालय में प्रार्थी ने अपने जमीन से कब्जा हटाने का प्रकरण आवेदन देकर दर्ज कराया, जिसके लिए सारी प्रक्रिया तहसील कार्यालय द्वारा कराई गई। यह प्रकरण 3 साल लंबित रहने के बाद नए नवेले तहसीलदार ने उसे खारिज कर दिया और उसमें लिखा कि सीमांकन में अनावेदक का हस्ताक्षर नहीं है। जब अनावेदक का हस्ताक्षर नहीं था, तो फिर सीमांकन क्यों एक्सेप्ट किया गया न्यायालय में और फिर सीमांकन करने वाले पर कारण बताओ नोटिस जारी होना था। गलती उनके अधीनस्थ कर्मचारी की और भरपाई करें प्रार्थी? जब पहली बार प्रकरण की फाइल तहसीलदार के समक्ष आई तो उन्होंने यह क्यों नहीं देखा कि प्रकरण में जमा किए गए दस्तावेज आधे अधूरे हैं। इसके लिए 3 साल का लंबा वक्त क्यों लगाया? क्या उचित सेटिंग नहीं हो पाई? कहीं उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, इस वजह से कुछ भी लिखकर प्रकरण को खारिज कर दिया गया? क्या ऐसे लंबित प्रकरण को तहसील कार्यालय में बेतुका तथ्यों पर खारिज किया जा सकता है? इस मामले में लिए गए फैसले ने राजस्व न्यायालयों के पूरी प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

टूट कर खड़े होने का मकसद मेरी बेटी है,मैं अतीत से कुछ भी नहीं बदलना चाहती हूं : जूही परमार

बीते ढाई दशकों से छोटे पर्दे पर एक्टिव जूही परमार ने टेलिविजन पर कई महिला किरदारों को मुखर किया। इन दिनों वे चर्चा में हैं महिला मुद्दों वाले नए शो कहानी हर घर की से...

टीवी,ओटीटी और फिल्मों में फेमिनिज़्म के मुद्दे देखने मिलते हैं, आपके लिए फेमिनिज्म क्या है?

मेरे लिए सबसे बड़ा फेमिनिज़्म ये है कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकूं। फेमिनिज्म का मतलब एक-दूसरे से कंपीट करना नहीं है। औरतों को खुद को मर्दों से बेहतर साबित करने की जरूरत नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब है, औरत की सादगी, उसकी नम्रता और उसका नर्चर करने वाला नेचर, केयर करने वाला गुण, मगर जब इस फेमिनिटी को उसके खिलाफ या उसे हीनता दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब औरत फट पड़ती है। सालों से दबाई और कुचली गई महिलाएं फेमिनिज्म का नारा बुलंद करने लगती हैं। इसके मूल में जाना जरूरी है। तभी परिवर्तन होगा।

लोगों का मानना है कि बीते कुछ समय से पुरुषों के खिलाफ महिलाओं द्वारा हिंसा किए जाने के जो मामले सामने आए हैं,उन्हें महिलाओं के खिलाफ एक नैरेटिव की तरह पेश किया गया?

मैं आपको एक बात बताऊं,नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें, तो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है न, उसकी तुलना में तो ये केसेज कुछ भी नहीं है। असल में क्या है न कि महिलाओं के साथ सालों से जो अत्याचार हो रहा है, उसे नॉर्मलाइज कर दिया गया है, तो अब जब महिलाओं द्वारा ऐसे केसेज सामने आ रहे हैं,तो लोगों को कल्चरल शॉक लग रहा है। हम इसे सपोर्ट नहीं कर रहे। हिंसा गलत है, चाहे वो औरत करे या मर्द, मगर कड़वी सचाई यह है कि महिलाओं ने सदियों से सहा है। अब जाकर औरतों ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं,जिसे हम जायज बिलकुल नहीं कह रहे। किसी के बेटे, भाई या पिता को मारना सरासर गलत है,मगर किसी की बेटी,किसी की बहन,किसी की मां भी तो सालों से मर ही रही है। हमें अगर बदलाव लाना है,तो जड़ से बदलना होगा।

एक महिला होने के नाते आपने हीनता का अहसास कब किया?

मुझे किसी ने हीनता का अहसास नहीं करवाया बल्कि मैंने अपनी कंडीशनिंग के कारण हीनता महसूस की। मेरी जिंदगी में जो भी उतार-चढ़ाव (उनका डिवोर्स) आए, उसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरी पिछली लाइफ थी। अपनी जिंदगी में जो झेल रही थी,तब कोई मुझसे कुछ नहीं कह रहा था। मगर मेरी कंडीशनिंग ने कुछ पलों के लिए मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ये मेरे साथ बहुत बुरी चीज हो गई है,अब लोग मुझे जज करेंगे। अब मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी? उस पल टूट कर खड़े होने का सबसे बड़ा मकसद मेरी बेटी रही है। वहीं से मेरी ग्रोथ,हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जहां से मैंने खुद को अपनी नजर से देखा। वही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था और आज मैं अपने अतीत से कुछ भी बदलना नहीं चाहती। आज मैं जो कुछ हूं, मुझे उस पर गर्व है।

आप के अंदर बेबाक और रिबेलियस होने का गुण कैसे आया?

मुझे लगता है कि मुझे किसी मकसद के साथ पैदा किया गया है (हंसती हैं) मेरे पेरेंट्स भी यही कहते हैं। मैं बचपन से ही ऐसी हूं। क्लास में भी अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा होता था, तो मैं आवाज उठाती थी। मुझे झांसी की रानी का नाम दिया गया था। मेरे प्रॉड्यूसर मुझे कॉल करके कहते, रानी लक्ष्मी बाई की जय हो। मेरी शूटिंग के सेट पर भी अगर किसी बुजुर्ग कलाकार या कैरेक्टर आर्टिस्ट के साथ कुछ अन्याय होता, तो मैं लड़ने खड़ी हो जाती।

सोशल मीडिया पर आपकी और आपकी बेटी की बॉन्डिंग के कई पोस्ट देखने को मिलते हैं?

मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, मेरी बेटी के साथ वाला। मैं बहुत ब्लेस्ड हूं, उस जैसी बेटी को पाकर। मेरी बेटी मुझसे निस्वार्थ प्यार करती है। ऊंचाई के जिस मयार पर वो मुझे रखती है, उसे लेकर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका मान रखूं। वो अपनी मां को बहुत ज्यादा इज्जत देती है। मैं इसलिए इतनी अच्छी मां हूं, क्योंकि मेरे पास इतनी प्यारी बेटी है।

आपका नया शो कहानी हर घर की में महिलाओं के साथ होने वाली प्रताड़नाओं की कहानी है और हाल ही में ग्रेटर नोएडा में भी निक्की दहेज कांड ने देश भर को हिला कर रख दिया?

विडंबना यही है कि हमें लगता है कि दहेज, मारपीट और प्रताड़ना नब्बे के दशक में हुआ करती थी, मगर आज भी अनगिनत लड़कियां और औरतें बहुत कुछ सह रही हैं। हम जब शो पर बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अत्याचार और अतिक्रमण का दौर आज भी चल रहा है। महिलाओं के पास कोई एक मुद्दा नहीं है। वे अनगिनत चीजों से जूझ रही हैं।

शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने 60 करोड़ की ठगी के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी

जिंदगी में कभी गलत नहीं किया,सच सामने आएगा

बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने 60 करोड़ रुपए की ठगी के मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। राज अपनी पंजाबी फिल्म 'मेहर' के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे थे। जब उनसे उनके और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी केस के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, बस इंतजार कीजिए और देखिए। यही जिंदगी है। हमने अब तक कुछ नहीं कहा क्योंकि हमें पता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। सच सामने आ जाएगा। हमने कभी जिंदगी में गलत नहीं किया और कभी करेंगे भी नहीं। बता दें कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर अगस्त में 60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दर्ज हुई थी। वहीं, हाल ही में इस मामले में आर्थिक आपराधिक शाखा राज कुंद्रा को समन भेजा था। उन्हें 15 सितंबर को आर्थिक आपराधिक शाखाके आगे पेश होकर बयान दर्ज करवाना होगा। इससे पहले राज कुंद्रा को 10 सितंबर को पेश होने के तलब किया गया था, हालांकि उन्होंने समय मांगा, जिसके बाद अब वो 15 सितंबर को बयान दर्ज करवाएंगे। जांच पूरी होने तक राज कुंद्रा भारत से बाहर नहीं जा सकेंगे। 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को 3 बार समन किया जा चुका है। दोनों ने वकील के जरिए जांच अधिकारियों से कहा कि वो लंदन में रहते हैं, जिसके चलते वो पेश नहीं हो सकेंगे। यही वजह रही कि उनकी तरफ से उनके वकील प्रशांत पाटिल हर बार हाजिर हुए। हालांकि,आर्थिक आपराधिक शाखाने कहा है कि वकील से उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिली है। इस मामले में 3 समन के बाद कपल के खिलाफ अगस्त में शिकायत दर्ज की गई थी।

क्या है 60 की धोखाधड़ी का पूरा मामला : अगस्त में मुंबई के एक बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई थी। दीपक कोठारी के मुताबिक, उनकी मुलाकात 2015 में एजेंट राजेश आर्या के जरिए शिल्पा और कुंद्रा से हुई थी। उस समय दोनों बेस्ट डील टीवी के डायरेक्टर थे और शिल्पा के पास कंपनी के 87% से ज्यादा शेयर थे। एक मीटिंग में तय हुआ कि शिल्पा और राज कुंद्रा की कंपनी को दीपक लोन देंगे। कंपनी के लिए 75 करोड़ रुपए का लोन मांगा था,जिस पर 12% सालाना ब्याज तय हुआ।

फिल्म रिव्यू-मिराई

त्याग,धर्म और भारतीय संस्कृति से सजी महागाथा,तेजा सज्जा की मासूमियत और दमदार एक्शन ने जीता दिल,क्लाइमेक्स में बड़ा राज

तेजा सज्जा की फिल्म मिराई भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक सुपरहीरो टेम्पलेट का ऐसा संगम है,जो बड़े परदे पर दर्शकों को नया अनुभव देता है। 2 घंटे 49 मिनट लंबी इस फिल्म का निर्देशन कार्तिक गट्टमनेनी ने किया है और यह अपने स्केल और विजुअल्स से प्रभावित करती है।

फिल्म की कहानी

कहानी की जड़ें सम्राट अशोक के काल से शुरू होती हैं। जब उन्होंने अपनी शक्तियों को नौ पवित्र ग्रंथों में बांट दिया,जिन्हें सैकड़ों सालों से इन्हें बचाने की जिम्मेदारी अलग-अलग पीढ़ियां उठाती रही हैं। अंबिका (श्रिया सरन) इन ग्रंथों की रक्षक हैं और अपने प्राणों की आहुति देकर 9वें ग्रंथ मिराई की रक्षा करती हैं। उनका बेटा वेद (तेजा सज्जा) आगे चलकर सुपर योद्धा बनता है, जिसे इन ग्रंथों की सुरक्षा करनी है। उसके सामने खड़ा है महावीर लामा (मनोज कुमार मांचू), जो अमरत्व पाने के लिए इन ग्रंथों को हासिल करना चाहता है।

फिल्म में एक्टिंग

तेजा सज्जा फिल्म की जान हैं। उनकी मासूमियत और इमोशन्स से लेकर एक्शन तक हर रंग परदे पर दिखाई देता है। मनोज कुमार मांचू खलनायक के तौर पर प्रभावशाली हैं और उनका स्क्रीन प्रेजेंस दमदार है। रितिका नायक ने कहानी में भावुकता और शांति का टच दिया है, वहीं श्रिया सरन त्याग और मां की ममता का प्रतीक बनकर दिल छू लेती हैं। जगपति बाबू और जयराम जैसे सीनियर कलाकारों ने भी अपनी मौजूदगी से कहानी को मजबूती दी है।

निर्देशन और तकनीकी पहलू

कार्तिक गट्टमनेनी का विजन बड़ा है। उन्होंने हिमालय, बनारस, हैदराबाद, जापान, तिब्बत और मोरक्को जैसी लोकेशंस को शानदार ढंग से पेश किया है, जो फिल्म को अंतरराष्ट्रीय अहसास देती हैं। एक्शन और मार्शल आर्ट्स का लेवल इंटरनेशनल क्वालिटी का है। हालांकि, फिल्म की लंबाई खलती है और कई जगह स्क्रीनप्ले ढीला पड़ जाता है। विजुअल्स का स्केल प्रभावित करता है, लेकिन कुछ युद्ध सीन्स उम्मीद के मुताबिक असरदार नहीं लगते और इमोशनल हिस्से भी हर बार गहरी पकड़ नहीं बना पाते।

फिल्म का संगीत : फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और गाने कहानी को मजबूती देते हैं। देशी वाद्यों और विदेशी ताल का मिला-जुला अंदाज कई सीन्स को ऊंचाई प्रदान करता है।

स्पेशल सरप्राइज और सीक्वल : फिल्म के अंत में राणा दग्गुबाती की सरप्राइज एंट्री होती है, जो यह साफ संकेत देती है कि मिराई एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत है। राणा का किरदार आगे की कहानी में गहराई और रहस्य जोड़ेगा। यह क्लिफहैंगर दर्शकों को सीक्वल के लिए उत्साहित करता है।

क्यों देखें यह फिल्म : अगर आपको पौराणिक कथाओं और सुपरहीरो फिल्मों का संगम पसंद है, तो मिराई आपके लिए है। विशाल स्केल, भव्य सेट डिजाइन और तेजा सज्जा का दमदार प्रदर्शन इसे खास बनाते हैं। हां, लंबाई और कुछ कमजोरियां खटकती हैं, लेकिन बड़े परदे पर यह अनुभव देखने लायक है।

खेल समाचार

हॉन्गकॉन्ग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट:सत्विक-चिराग सेमीफाइनल में पहुंचे,मलेशियाई जोड़ी को तीन सेट में हराया

नई दिल्ली,12 सितम्बर 2025। हॉन्गकॉन्ग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेन्स डबल्स में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी सेमीफाइनल में जगह बना ली है,वहीं लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की जोड़ी जुनैदी अरिफ और रॉय किंग याप को रोमांचक तीन गेम वाले मुकाबले में हराया।

कांटे का रहा मुकाबला

पहले गेम में सत्विक-चिराग ने मलेशियाई जोड़ी को 21-14 से आसानी से हरा दिया। लेकिन दूसरे गेम में वे थोड़े चूक गए और 20-22 से हार गए,जिससे स्कोर 1-1 हो गया। फिर तीसरे और निर्णायक गेम में भारतीय जोड़ी ने शानदार वापसी की। वे 21-16 से जीतकर टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली। यह मैच एक घंटे से ज्यादा समय तक चला। इसमें सात्विक-चिराग शुरू से मैच में अपनी पकड़ बनाए रखा। अब सात्विक-चिराग सेमीफाइनल में चाइनीज ताइपेई के चेन चेंग कुआन और लिन बिंग-वेई का सामना करेंगे।

थाईलैंड की जोड़ी को हरा कर क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया : इससे पहले, सत्विक-चिराग ने थाईलैंड के पीराटचाई सुकफुन और पक्कापोन टीरारतसाकुल को हरा कर क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया था। उन्होंनें एक घंटे 3 मिनट तक चले मुकाबले में एक गेम से पिछड़ने के बाद 18-21, 21-15, 21-11 से हराकर अंतिम-8 में प्रवेश किया था।

लक्ष्य सेन ने प्रणय को हराया

भारतीय सिंगल्स खिलाड़ी और वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर-20 लक्ष्य सेन ने भी शानदार खेल दिखाते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने अपने ही देश के खिलाड़ी एचएस प्रणय (वर्ल्ड रैंक 34) को 15-21, 21-18, 21-10 से मात दी। इस मैच में लक्ष्य की शुरुआत धीमी रही और प्रणय ने पहला गेम 21-15 से जीत लिया। हालांकि दूसरे गेम में लक्ष्य ने वापसी की। 11-9 से पीछे रहने के बाद उन्होंने शानदार खेल दिखाया और 21-18 से गेम जीत लिया। निर्णायक गेम में लक्ष्य ने पूरी तरह से मैच पर पकड़ बना ली।

रिकर्व में भारत फिर से खाली हाथ,ओलंपिक चैंपियन लिम से हारीं गाथा खडके

नई दिल्ली,12 सितम्बर 2025। रिकर्व तीरंदाजी में विश्व पदक के लिए भारत का लंबा इंतजार और बढ़ गया, क्योंकि देश की आखिरी उम्मीद 15 वर्षीय गाथा खडके शुक्रवार को विश्व चैंपियनशिप में प्री-क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर एक लिम सी-हियोन से हार गईं, जिससे टूर्नामेंट में उनका अभियान समाप्त हो गया। पेरिस ओलंपिक की तिहरी स्वर्ण पदक विजेता कोरियाई खिलाड़ी ने घरेलू दर्शकों के सामने आसानी से मैच 6-0 से जीत लिया। हालांकि, एकतरफा हार के बावजूद विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण करते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल तक गाथा खडके का निडर प्रदर्शन भविष्य के लिए आशा की किरण जगाता है, जहां भारत लगातार असफल रहा है। भारत ने आखिरी बार 2019 में विश्व चैंपियनशिप में रिकर्व पदक जीता था, जब तरुणदीप राय, अतनु दास और प्रवीण जाधव की पुरुष टीम ने डेन बॉश में रजत पदक जीता था। लिम ने शुरुआत में तीन परफेक्ट 10 लगाकर नियंत्रण हासिल किया और युवा भारतीय खिलाड़ी केवल दो 9 और एक 8 ही लगा सकीं, जिससे उन्हें पहला सेट 26-30 से हारना पड़ा। शानदार नियंत्रण दिखाते हुए लिम ने दूसरे सेट में गति धीमी करने का फैसला किया, लेकिन फिर भी गाथा से आगे रहीं, जो दो 8 और एक 9 पर सिमट गईं। लगातार तीसरे संस्करण में भारतीय रिकर्व तीरंदाज खाली हाथ लौटे। दीपिका कुमारी के एक और निराशाजनक प्रदर्शन ने इस कहानी को और भी पुख्ता कर दिया, जो पहले ही दौर में बाहर हो गईं। छह बार विश्व चैंपियनशिप में भाग ले चुकीं और चार बार की ओलंपियन दीपिका अभी भी दोनों स्पर्धाओं में अपने पहले पदक की तलाश में हैं।

दलीप ट्रॉफी फाइनल:यश-रजत के शतक दूसरे दिन सेंट्रल जोन का स्कोर 384/5 साउथ जोन 149 रन पर ऑलआउट

नई दिल्ली,12 सितम्बर 2025। 2025 दलीप ट्रॉफी फाइनल के दूसरे दिन स्टंप्स तक सेंट्रल जोन ने 5 विकेट खोकर 384 रन बना लिए हैं। टीम ने साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी में 235 रन की बढ़त ले ली है। शुक्रवार को सेंट्रल जोन ने अपनी पहली पारी को 50/0 के स्कोर से आगे बढ़ाया। कप्तान रजत पाटीदार 101 रन बनाकर आउट हुए। यश राठौड़ 137 और सारांश जैन 47 रन बनाकर नाबाद है। उनके अलावा, दानिश मालेवार 53,ओपनर अक्षय वाडकर 22, शुभम शर्मा 6 और उपेंद्र यादव 5 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले, बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर गुरुवार को साउथ जोन पहली पारी में 149 रन पर ऑलआउट हो गई। सेंट्रल जोन ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी। सारांश जैन को 5 विकेट साउथ जोन पहली पारी में 149 रन पर ही सिमट गई। टीम के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। टीम के लिए तन्मय अग्रवाल ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। उनके अलावा सलमान निजार 24, अंकित शर्मा 20, रिकी भुई 15 और एमडी निधेश 12 रन बनाए। सेंट्रल जोन की ओर से सारांश जैन ने 5 और कुमार कार्तिकेय ने 4 विकेट झटके। साउथ जोन ने 13 बार दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है, जबकि सेंट्रल जोन ने 6 बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है। दलीप ट्रॉफी की बादशाहत वेस्ट जोन के पास मुंबई शुरुआत से भारतीय क्रिकेट का सेंटर रहा है। मुंबई वेस्ट जोन में आता है, लिहाजा दलीप ट्रॉफी में वेस्ट की टीम को इसका काफी फायदा भी हुआ। सबसे ज्यादा 19 बार वेस्ट जोन ने ही खिताब जीता है। टीम ने शुरूआती चारों सीजन अपने नाम किए थे। नॉर्थ जोन 18 बार इस ट्रॉफी को जीत चुकी है। 27वीं बार आमने-सामने हैं दोनों टीमें साउथ जोन और सेंट्रल जोन 27वीं बार आमने-सामने हैं। इससे पहले,दोनों टीमों के बीच 26 मुकाबले खेले जा चुके हैं। दोनों टीमों ने 8-8 जीतें हैं। वहीं, 10 मैच ड्रॉ रहे हैं।

नक्सल ऑपरेशन की बड़ी सफलता

1 करोड़ का इनामी नक्सली समेत 10 ढेर

बीजापुर,12 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। बुधवार को राज्य पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा द्वारा चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन में मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण समेत 10 नक्सली ढेर कर दिए गए है। मोडेम बालकृष्ण पर 1 करोड का इनाम घोषित था।

कौन था मोडेम बालकृष्ण

मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण नक्सली संगठन का शीर्ष कमांडर था। वह ओडिशा स्टेट कमेटी में अहम जिम्मेदारी संभाल रहा था। उस पर हत्या, लूट, पुलिस बल पर हमला जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज थे। मोडेम बालकृष्ण पर सरकार ने 1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था। माना जाता है कि वह कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड भी रहा है।

नक्सल गतिविधियों का पुराना गढ़ है गरियाबंद

गरियाबंद जिला लंबे समय से नक्सल प्रभावित इलाकों में शामिल रहा है। यहां अक्सर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होती रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लगातार अभियान के चलते नक्सली गतिविधियों में कमी देखने को मिली है।

सुरक्षाबलों की कार्रवाई जारी

सुरक्षा बलों का कहना है कि मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है और उनके कब्जे से हथियार, दस्तावेज और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर विस्फोटक बरामद

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में आज शुक्रवार की सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गये हैं । मौके से दो वर्दीधारी नक्सली के शव के साथ 303 रायफल, विस्फोटक सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की गई हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने इसकी पुष्टि करओ हुए बताया कि क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, इसी दौरान आज सुबह मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों ओर से लगभग दो घंटे की गोलाबारी के बाद अब तक सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। चूंकि ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या तथा अन्य संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की जा सकती। ऑपरेशन पूर्ण होने के पश्चात विस्तृत रिपोर्ट अलग से साझा की जाएगी।

बस्तर में तेज रफ्तार बोलेरो और एक कार में भीषण भिड़ंत,दो लोगों की जलकर मौत...

जगदलपुर,12 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। देर रात नेशनल हाईवे -43 पर बड़ा हादसा हो गया। बड़े किलेपाल के पास तेज रफ्तार बोलेरो और कार की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतना भीषण था कि हादसे के बाद दोनों वाहन आग की लपटों से घिर गए। इस हादसे में कार सवार तीन में से दो लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। बोलेरो चालक ने गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पायी है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना कोड़ेनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। एक तेज रफ्तार कार और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। घटना इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। इस घटना में कार में सवार 3 में से 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग के बुझने पर 2 कंकाल भी बरामद किये गये हैं। इस घटना में घायल एक युवक को मेकाज रेफर किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जगदलपुर से दंतेवाड़ा जा रही बोलेरो और दंतेवाड़ा की ओर से जगदलपुर आ रही कार में रात करीब एक बजे के आसपास टक्कर हुई है। यह हादसा किलेपाल के पास हुआ है। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। पीछे सीट में सवार एक युवक किसी तरह अपनी जान बचाते हुए कार से बाहर निकल गया, जबकि कार में ड्राइवर सीट में बैठा युवक और बगल की सीट में बैठा युवक निकल ही नहीं पाए। इससे दोनों जिंदा ही जल गए। बोलेरो में सवार युवक भी किसी तरह बाहर निकल गया। हादसे की सूचना पर रास्ते में चल रहे दूसरे वाहन के चालकों ने इस घटना की जानकारी पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड दी। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नही हो पाई है। अस्पताल में भर्ती युवक से पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि घटना कैसे हुई और मरने वाले युवक कौन थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने जेडी को किया सस्पेंड,इन्हें मिला अतिरिक्त प्रभार मंत्री गजेंद्र यादव की बड़ी कार्रवाई

रायपुर,12 सितम्बर 2025। स्कूल शिक्षा विभाग ने दुर्ग शिक्षा संभाग के संयुक्त संचालक हेमंत उपध्याय को सस्पेंड कर दिया है। अभी-अभी जारी आदेश में लिखा है कि सरगुजा में पोस्टिंग के दौरान उपध्याय के कार्यों में अनियमितता की पुष्टि हुई है। तथा उपध्याय ने वहां स्वेच्छरिता और अनुशासनहीनता की। हेमंत उपध्याय का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के खिलाफ है। उपध्याय को निलंबित करते हुए उन्हें डीपीआई में अटैच किया गया है। हालांकि,इससे पहले भी वे सहायक शिक्षकों के प्रमोशन के बाद शिक्षकों का ट्रांसफर मामले में सस्पेंड होकर लंबे समय तक डीपीआई में अटैच रहे थे। सरकार बदलने के बाद उन्हें फिर से जेडी की पोस्टिंग मिल गई थी। दुर्ग से गजेंद्र यादव के स्कूल शिक्षा मंत्री बनने के बाद हेमंत उपध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह पहली कार्रवाई की है। उन्होंने डीपीआई में पोस्टेड डिप्टी डायरेक्टर आरएल ठाकुर को दुर्ग संभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस दृष्टि से कि हेमंत उपध्याय राजनीतिक पहुंच वाले अफसर हैं।

पूर्व मंत्री कवासी लखमा को नहीं मिली राहत!

हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका..

बिलासपुर,12 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि लखमा पर लगे आरोप गंभीर आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं और जांच अभी जारी है। ऐसे में उन्हें जमानत दिए जाने से सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

क्या है पूरा है मामला

कवासी लखमा को प्रवर्तन निदेशालय (प्रवर्तन निदेशालय) ने 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि लखमा ने वर्ष 2019 से 2023 के बीच राज्य में एफएल-10ए लाइसेंस नीति लागू कर अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा दिया। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस नीति के जरिए बने शराब सिंडिकेट से उन्हें हर महीने लगभग 2 करोड़ की अवैध आय होती थी। कुल मिलाकर यह राशि 72 करोड़ से अधिक आंकी गई है।

पूर्व मंत्री कवासी लखमा का पक्ष

लखमा ने अपनी याचिका में कहा कि यह मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और उनके खिलाफ आरोप सह-अभियुक्तों के बयानों पर आधारित हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और सह-अभियुक्तों, अरुणपति त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनिल टुटेजा और अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

मामले में अदालत का फैसला

मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कावसी लखमा की दलीलों का कड़ा विरोध किया और अदालत को बताया कि लखमा इस पूरे षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि यह मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।

सीएम साय ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जीएसटी पर मिली राहत की जानकारी दी

रायपुर,12 सितम्बर 2025। सीएम साय ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीएसटी पर मिली राहत की जानकारी दी। आम आदमी के जीवन में सुधार लाने और छोटे व्यापारियों और व्यापारियों सहित सभी के लिए व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी- सरकार अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लाएगी, जिससे आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा। यह आपके लिए दिवाली का तोहफा होगा। उन्होंने कहा कि सुधारों से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ होगा, जबकि भारत की दीर्घकालिक वृद्धि को सुदृढ़ किया जाएगा। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप जीएसटी परिषद ने एक व्यापक सुधार पैकेज की अनुशंसा की है जिसमें सरलीकृत दो-स्लैब संरचना (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) के साथ दर युक्तिकरण, आम आदमी, श्रम-केंद्रित उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सेक्टरों में दरों में कटौती शामिल है। ये अनुशंसाएं जीएसटी परिषद के सभी सदस्यों के बीच जीएसटी को सरल, निष्पक्ष और अधिक विकास-उन्मुख बनाने के लिए आम सहमति पर आधारित हैं।

मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए बस पास सुविधा होगी बंद,कर्मचारियों ने जताई नाराजगी,आंदोलन की दी चेतावनी

रायपुर,12 सितम्बर 2025। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए 1 अक्टूबर से मुफ़्त बस पास सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यह निर्णय वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है। इस परिवर्तन से जुड़े कर्मचारियों में असमंजस और असंतोष का माहौल है। उनका कहना है कि रायपुर से नवा रायपुर रोजाना आना-जाना आसान नहीं है-एक ओर बस किराया बढ़ रहा है,वहीं दूसरी ओर मासिक भत्ता 100 रुपये ही रखा गया है, जो उन्हें पर्याप्त नहीं लगता। कुछ कर्मचारियों ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसे कर्मचारी हितों को कम प्राथमिकता देना बताया है और सुझाव दिया है कि या तो पुरानी बस सुविधा फिर से शुरू की जाए, या विकल्प स्वरूप सभी को 2000 रुपये प्रति माह का वाहन भत्ता दिया जाए।

सरकारी आवास में नेता-अधिकारी रहते हैं,उन्हें नोटिस क्यों नहीं : भूपेश

रायपुर,12 सितम्बर 2025। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार दिल्ली के रवना हुए। एयरपोर्ट पर उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। निगम की ओर से भेजे गए संपत्ति कर के नोटिस से लेकर उन्होंने कहा कि अजीब बात है कि केवल मुझे ही नोटिस भेजा गया। शासकीय आवासों में नेता और अधिकारी भी रहते हैं, उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया गया? हाल ही में हुई नक्सल मुठभेड़ को लेकर भूपेश बघेल ने जवानों की सफलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि नक्सलवाद खत्म हो, मगर यह भी ध्यान रखा जाए कि गरीब आदिवासी न मारे जाएं। कई घटनाओं में निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताया गया है। भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले साल जो धान खरीदी हुई थी, वह अब तक राइस मिलों में जमा नहीं हुआ है और धान अभी भी संग्रहण केंद्रों में पड़ा है। सितंबर-अक्टूबर के बाद अर्ली वैरायटी का धान आने लगेगा, लेकिन खरीदी प्रभावित होगी। ऊपर से खाद की कमी, बिजली कटौती और मनमानी हो रही है। किसानों का रजिस्ट्रेशन भी सही से नहीं हो रहा। खासकर नगर पंचायत और पालिका क्षेत्रों में किसी का पंजीयन हुआ है, तो किसी का नहीं। जिन किसानों की जमीन दो गांवों में है, उनका भी एक गांव की जमीन का पंजीयन हो रहा है और दूसरे का नहीं। ऐसे में किसान धान कहां बेचेंगे? यह बहुत गंभीर स्थिति है। समय भी कम बचा है और बड़ी संख्या में किसान परेशान और आने वाले दिनों में धान खरीदी को लेकर अफरा तफरी मचने वाली है।

राज्योत्सव में पहली बार वायु सेना का हवाई करतब,सूर्यकिरण एरोबेटिक की टीम तैयार....

रायपुर,12 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती यानि 25वें स्थापना वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित होने वाले राज्योत्सव 2025 में भारतीय वायु सेना का अद्भुत शौर्य प्रदर्शन राज्यवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। यह पहला अवसर होगा जब राज्योत्सव के मंच से वायु सेना की प्रतिष्ठित सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम आसमान में रंग-बिरंगे करतब दिखाएगी।

क्या है सूर्यकिरण एरोबेटिक : सूर्यकिरण एरोबेटिक की टीम अपने सटीक और रोमांचक हवाई प्रदर्शन के लिए विश्वप्रसिद्ध है। 8 हॉक जेट विमानों से लैस यह टीम आकाश में त्रिशूल,पंखुड़ी,हार्ट शेप और राष्ट्रीय ध्वज जैसे अद्भुत आकाशीय चित्रों का निर्माण कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते है। साथ ही वायु सेना के विशेष हेलीकॉप्टर भी इस प्रदर्शन में भाग लेंगे, जो छत्तीसगढ़ के गौरवमयी अवसर को और भव्य बनाएंगे।

तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक : राज्योत्सव में वायु सेना के शौर्य प्रदर्शन को लेकर मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विमानन विभाग एवं भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने डिजिटल प्रेजेंटेशन के जरिए तकनीकी और लॉजिस्टिक तैयारियों की जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव श्री साहू ने इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय और समयबद्ध तैयारी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों को देश की वायु शक्ति का यह जीवंत प्रदर्शन देखने का एक दुर्लभ अवसर मिलेगा, जिसे हर स्तर पर सुरक्षित और भव्य बनाया जाना चाहिए।

5 चॉइस सेंटर संचालकों के लाइसेंस निरस्त

बलौदाबाजार,12 सितम्बर 2025। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार कार्य में लापरवाही बरतने वाले जिले 5 चॉइस सेंटर संचालकों के लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से चॉइस सेंटर संचालको को पूर्ण दस्तावेज अपलोड करना होता है।अपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने पर समय पर प्रमाण पत्र जारी नही होता है और आवेदकों को केंद्र का चक्कर लगाना पड़ता है। अपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने वाले कुल 15 लोक सेवा केंद्र व चॉइस सेंटर संचालकों को इस सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया जिसमे से 5 लोक सेवा केंद्र व चॉइस सेंटर संचालको का लोक सेवा केंद्र का लाईसेंस निरस्त किया गए एवं कुल 10 लोक सेवा केंद्र,चॉइस सेंटर संचालक को अंतिम चेतवानी पत्र जारी किया गया है। लाइसेंस निरस्त होने वाले चॉइस सेंटर संचालकों में विकासखंड सिमगा ग्राम हिरमी के अंगिता वर्मा, ग्राम कटगी के अनवर रजा, विकासखंड बलौदाबाजार ग्राम भरसेला के यानेश तिवारी, ग्राम क़सियारा के मनहरण,ग्राम पनगांव के नोखराम ध्रुव शामिल हैं।

हाई कोर्ट ने खारिज की सांसद भोजराज नाग की याचिका

रायपुर,12 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कांकेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भोजराज नाग की एक अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका को शुरुआती स्तर पर ही अस्वीकार करने की मांग की थी। यह फैसला न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने 11 सितंबर को सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका में लगाए गए आरोपों में पर्याप्त तथ्य और साक्ष्य मौजूद हैं, जिससे यह मामला मेरिट्स पर सुनवाई के योग्य बनता है। इस पूरे मामले की शुरुआत 18 जुलाई 2024 को हुई, जब कांकेर निवासी बिरेश ठाकुर ने लोकसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़,मतगणना में गड़बड़ी और वोटिंग डेटा के ट्रांसमिशन में देरी जैसी गंभीर अनियमितताएं हुईं। उन्होंने कांकेर संसदीय क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान और कई बूथों पर पुनः मतगणना की मांग की है। याचिका में विशेष रूप से गोंडरदेही और डोंडी लोहारा सहित कुछ विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में वोटों के अंतर और डेटा ट्रांसमिशन में हेरफेर की आशंका जताई गई है। सांसद भोजराज नाग ने इस याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसमें भ्रष्ट आचरण का कोई स्पष्ट आरोप नहीं है और यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81, 82 और 83 का उल्लंघन करती है। उन्होंने यह भी दलील दी कि चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया है और याचिका वकील के माध्यम से दाखिल की गई है, जबकि उसे खुद याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया जाना चाहिए था। हालांकि, हाई कोर्ट ने इन आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने माना कि याचिका में सभी आवश्यक तथ्य और कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को पक्षकार बनाना अनिवार्य नहीं है और याचिका विधिवत तरीके से दाखिल की गई है, जिस पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन नवंबर 2025 को होगी।

वोट चोरी के मुद्दे पर 16-17-18 को कांग्रेस का आंदोलन

ट्राइबल डिपार्टमेंट में 50 हजार की रोटी मेकर मशीन 8 लाख में खरीदी : दीपक बैज

रायपुर,12 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने शुक्रवार को सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, नक्सलवाद और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की आगामी वोट छोड़ गद्दी छोड़ पदयात्रा की घोषणा की। बैज ने कहा कि 16 सितंबर को रायगढ़ से,17 सितंबर को कोरबा-मुंगेली और 18 सितंबर बेमेतरा-कवर्धा-दुर्ग में वोट छोड़ गद्दी छोड़ रैली निकाली जाएगी।

रोटी बनाने की मशीन घोटाला

पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि ट्राइबल विभाग से हॉस्टल के लिए खरीदी मशीन को लेकर एक और बड़ा घोटाला समाने आया है। बैज ने कहा 50-60 हजार की मशीन को 7.95 लाख में खरीदा गया है। इसी तरह पूर्व में भी ट्राइबल विभाग में तय कीमत से ज्यादा महंगे दाम पर सामानों की खरीदी की गई है।

बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट पर सवाल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कहा कि सरकार ने करोड़ों रुएय खर्च कर बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया। सरकार का दावा है कि 967 करोड़ रुपए का निवेश आया है। सरकार बताए कि इस प्रस्ताव में कितनी कंपनियों के साथ एमओयू किया गया? इन कंपनियों की ओर से कितने दिनों में निवेश प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा? निवेश के लिए एमओयू करने वाली कंपनियों का प्रोफाइल भी सरकार सार्वजनिक करे। बैज ने कहा कि सरकार ने एक दर्जन से अधिक शेल कंपनियों से एमओयू करने की तैयारी है। यह शासकीय जमीन हड़पने का षड़यंत्र भी हो सकता है। इन्वेस्टर कनेक्ट में एनएमडीसी और भारत सरकार की रेल और सड़क परियोजनाओं को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ठोस प्रस्ताव नहीं है। एनएमडीसी और भारत सरकार के रेल और सड़क परियोजनाएं तो पहले से प्रस्तावित है। इनमें इन्वेस्टर कनेक्ट की क्या उपलब्धि है?

नक्सलवाद पर सरकार को घेरा

पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि नक्सल गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, शिक्षा दूतों की हत्या चिंता का विषय है। वही गरियाबंद में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता पर बैज ने जवानों को बधाई दी है। वहीं मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म में सरकार के दावे को लेकर कहा कि मार्च के बाद ही कुछ कहूंगा।

एसआईआर विवाद पर पलटवार

गृहमंत्री विजय शर्मा के बयान पर कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, बिहार में जिंदा लोगों को मृत दिखाया गया। नाम काटने की गड़बड़ी पर उन्होंने जांच की मांग की है।

कहां है 50 लाख मीट्रिक टन यूरिया?

दीपक बैज ने कहा कि केंद्रीय उर्वरक मंत्री नड्डा से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि सितंबर महीने में 50 हजार मीट्रिक टन यूरिया केन्द्र की ओर से भेजा जाएगा। सरकार ने कहा था सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह तक 30 हजार मीट्रिक टन यूरिया सोसायटियों में पहुंच जाएगा।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा साईं ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह*(पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)